मेट्रो Rays

आगे रखने का वादा

रांची, शनिवार, 21 नवंबर 2026

संवत 2083, कार्तिक शुक्ल 12 मूल्य-2 रुपये

वर्ष-10, अंक 75 , पृष्ठ-8, RNI No.-JHAHIN/2017/75028

सांध्य दैनिक



4 ▸▸ समुद्री मार्गों को सुचारु रखने में भारत की भूमिका

मातृभूमि के गाने मदिरापान में सलमान खान के शानदार डांस मूव्स देख नेटिजेंस हुए दीवाने ◂◂ 6

गुमला तेज हेडलाइट से बिगड़ा बाइक का संतुलन, दो दोस्तों की मौत, तीसरा गंभीर



गुमला: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के डडगांव मोड़ के पास देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रहे वाहन की हेडलाइट की रोशनी पड़ने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।

धान की मड़ाई कर लौट रहे थे तीनों दोस्तः जानकारी के अनुसार, तीनों दोस्त एक ही डोमिनार बाइक पर सवार होकर रातू गम्हरिया गांव में धान की मड़ाई (थ्रेसिंग) करने गए थे। बारिश के कारण उन्हें घर लौटने में काफी देर हो गई। रात में डडगांव मोड़ के पास सामने से आ रहे एक वाहन की तेज हेडलाइट की रोशनी बाइक चालक की आंखों पर पड़ी। इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क पर गिर गई।

दो युवकों की मौके पर मौतः हादसे में पुनीत एक्का (पिता स्वर्गीय कमला एक्का) और विकास एक्का (पिता स्वर्गीय वाल्टर एक्का) की मौत हो गई। दोनों रायडीह प्रखंड के तुरमुंगा दुमरटोली (मझटोली) गांव के निवासी थे। वहीं, घायल कुलदीप टोप्पो सुनील टोप्पो का पुत्र है। एक ही गांव के दो युवकों की मौत से इलाके में मातम पसरा है।

घायल युवक गुमला सदर अस्पताल रेफरः हादसे में कुलदीप के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उसके शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तीनों को चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां चिकित्सक डॉ. प्रभात ने पुनीत और विकास को मृत घोषित कर दिया। कुलदीप को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

हेलमेट नहीं पहनने और तेज रफ्तार की जांचः सूचना मिलने पर चैनपुर थाने के एसआई विजय उरांव और एएसआई धर्मपाल लुगुन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है।

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाइक सवार युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था और बारिश के कारण सड़क पर फिसलन भी थी।

गुमला एसपी अनुपम किशोर ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से लगातार सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद युवा यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण इस तरह के जानलेवा हादसे हो रहे हैं।

तिलक समारोह से लौट रही बाराती कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, पांच गंभीर

पलामूः तिलक समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बिसफुट्टा पुल के पास शुक्रवार देर रात बारातियों से भरी कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी तिलक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। मृतक की पहचान विश्रामपुर थाना क्षेत्र के बघमनवा गांव निवासी सरजू पाल के 35 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र पाल के रूप में हुई है। समारोह से लौटते समय हुआ हादसाः परिजनों के अनुसार, कार में सवार सभी छह लोग नावाबाजार थाना क्षेत्र के रबदा गांव से सतबरवा थाना क्षेत्र के पोलपोल गांव में आयोजित तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह से लौटने के दौरान बिसफुट्टा पुल के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सभी छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और सभी घायलों को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने धर्मेंद्र पाल को मृत घोषित कर दिया। पांच अन्य घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

रांची में दिनभर छाया अंधेरा, बारिश और ठंड से जनजीवन अस्त-व्यस्त,बाजारों में भी पसरा सन्नाटा



गुलाम शाहिद

रांचीः राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में शनिवार को मौसम का मिजाज ऐसा रहा कि दिन में ही रात जैसा नजारा देखने को मिला। लगातार रिमझिम बारिश, घने बादलों और ठंड के कारण लोग घरों में दुबके रहे। सड़कों पर आम दिनों की तुलना में आवाजाही कम रही। गर्म कपड़ों में लिपटे लोग जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले।

बारिश और ठंड का असर बाजारों पर भी देखने को मिला। दुकानदार ग्राहकों की राह देखते रहे, जबकि खरीदारी करने वालों की संख्या काफी कम रही। कई कारोबारी मौसम की खराबी से परेशान नजर आए। दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में उदासी भरा माहौल रहा।

बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान 'अकवान' के प्रभाव से रांची समेत झारखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा। शनिवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 14 विमान रद्द कर दिए गए। एक साथ बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने से देश के 10 शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पर यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में बदलाव करना पड़ा। मौसम की बेरुखी ने आम जनजीवन से लेकर कारोबार और हवाई सेवाओं तक को प्रभावित किया। बारिश और ठंड के बीच राजधानीवासी दिनभर मौसम के सुधरने का इंतजार करते रहे।

रांची एयरपोर्ट से 14 उड़ानें रद्द, 10 शहरों के यात्री परेशान



रांचीः बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान 'अकवान' के कारण रांची समेत झारखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम के कारण शनिवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 14 विमान रद्द कर दिए गए। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से 10 शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

दिल्ली की चार और कोलकाता की दो उड़ानें रद्दः रद्द की गई उड़ानों में सबसे अधिक चार फ्लाइट रांची-दिल्ली रूट की हैं। इनमें फ्लाइट नंबर 2038, 2219, 2286 और 6274 शामिल हैं। इसके अलावा रांची-कोलकाता सेक्टर की दो उड़ानें (7466 और 7468) भी रद्द की गईं।

दिल्ली और कोलकाता के अलावा आठ अन्य शहरों की एक-एक उड़ान रद्द हुई। इनमें रांची-हैदराबाद (398), रांची-पटना (925), रांची-मुंबई (6088), रांची-भुवनेश्वर (7726), रांची-चेन्नई (209), रांची-अहमदाबाद (6654), रांची-पुणे (761) और रांची-बेंगलुरु (6799) की उड़ानें शामिल हैं।

ठंडी हवाओं से बढ़ी कनकनी, संथाल में भारी बारिश का अलर्ट

रांचीः चक्रवाती तूफान 'अकवान' के असर से झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में शुक्रवार से आसमान में बादल छाए हैं और रुक-रुककर बारिश हो रही है।

शनिवार सुबह रांची में आसमान घने बादलों से ढका रहा। ठंडी हवाओं के कारण लोगों को कनकनी महसूस हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले दो दिनों तक राज्य के कई इलाकों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

बेमौसम बारिश से किसानों की बढ़ी चिंताः चक्रवाती तूफान के असर से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा नुकसान तैयार धान की फसल को होने की आशंका है। जिन किसानों ने धान काटकर खेतों में छोड़ दिया है, उनकी फसल बारिश में भीग रही है। वहीं, तेज हवा और बारिश के कारण खेतों में खड़ी तैयार धान की फसल गिरने का खतरा भी बढ़ गया है।

मौसम विभाग के पूवार्नुमान के अनुसार, 22 नवंबर को भी झारखंड में बादल छाए रहेंगे। राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या मेघ गर्जन की प्रबल संभावना है। वहीं, 23 नवंबर को मौसम साफ होने का अनुमान है। 24 और 25 नवंबर की सुबह राजधानी समेत कई इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरे के साथ ठंड बढ़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

साथी सैनिक की गोली से घायल जवान भी होगा वॉर इंजरी पेंशन का हकदार



नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सैनिकों की पेंशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वॉर इंजरी एलिमेंट यानी युद्ध के दौरान लगी चोट के आधार पर मिलने वाली बढ़ी हुई पेंशन का लाभ पाने के लिए जवान का दुश्मन की गोली से घायल होना जरूरी नहीं है। सैन्य अभियानों के दौरान अपने ही हथियार से गलती से गोली चलने या अपनी सेना के साथियों की फायरिंग में घायल होने वाले जवान भी इस पेंशन के हकदार हो सकते हैं। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने कहा कि यदि जवान सेना के निर्धारित आदेशों के दायरे में आने वाली परिस्थितियों में घायल होता है, तो उसे ह्यवुंडेड बैटल कैजुअल्टीह्न यानी युद्ध के दौरान घायल सैनिक की श्रेणी में रखा जा सकता है।

अदालत ने बताया कि सेना की नीति में ऐसी दो परिस्थितियों को मान्यता दी गई है। पहली, गोली या उसके किसी टुकड़े से गलती से लगी चोट और दूसरी, अपनी ही सेना के जवानों की फायरिंग से लगी चोट। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि घटना दुश्मनों या उग्रवादियों के खिलाफ किसी सैन्य अभियान के दौरान हुई हो।

पीठ ने कहा कि सर्विस हथियार से गलती से गोली चलने की घटना के पीछे किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा जरूरी नहीं है। अचानक झटका लगने, गिरने, ट्रिगर किसी वस्तु में फंसने, अनजाने में ट्रिगर दबने या तकनीकी खराबी के कारण भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं।

न्यायाधीशों ने ऐसी दुर्घटनाओं को जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने यानी सेल्फ-इन्फ्लिक्टेड इंजरी से अलग माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनजाने में हुई ऐसी घटनाओं के आधार पर किसी सैनिक को बढ़ी हुई पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

यह फैसला सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक या ऑपरेशन पराक्रम के दौरान वह घायल हो गए थे। सैन्य अभियान के दौरान उनके अपने ही हथियार से गलती से गोली चल गई, जो उनकी जांघ के आर-पार निकल गई। इस घटना में उनकी फीमोरल नस को नुकसान पहुंचा और उन्हें 40 फीसदी विकलांगता हो गई।

हालांकि, देवी सिंह को सामान्य विकलांगता पेंशन यानी डिसेबिलिटी एलिमेंट का लाभ दिया गया था, लेकिन बढ़ी हुई वॉर इंजरी एलिमेंट पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था। उनकी मांग को आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने भी खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पलटते हुए देवी सिंह को बढ़ी हुई युद्ध चोट पेंशन का हकदार माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि सैन्य अभियान के दौरान अपने ही हथियार से अनजाने में गोली चलने की घटना को भी सेना के नियमों के तहत युद्ध में लगी चोट माना जा सकता है।

आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख में पहली बार पंचायत-निकाय चुनाव, वोट डालने के लिए घरों से निकले लोग

नई दिल्ली : केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहली बार नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हो रहा है। लेह नगर पालिका की सभी 21 सीटों और कारगिल नगर पालिका की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लद्दाख में लेह और कारगिल दो नगर पालिकाएं हैं। लेह में 21 वार्ड और कारगिल में 17 वार्ड हैं। कारगिल नगर पालिका के चार पार्षद निर्विरोध चुने जा चुके हैं। लेह नगर पालिका में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। वहीं, कारगिल में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मजबूत स्थिति में हैं। लेह नगर पालिका की 21 सीटों के लिए कुल 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। लद्दाख में पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश की कुल 192 पंचायतों में से 55 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि 137 सरपंच सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी तरह, कुल 1428 पंच सीटों में से 1186 पंच निर्विरोध चुने गए हैं और अब केवल 242 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नगर पालिका चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी और पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में कराए जा रहे हैं। नगर पालिका चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर हो रहे हैं, जबकि पंचायत चुनाव गैर-दलीय आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों को इन चुनावों में भारी मतदान की उम्मीद है, क्योंकि 5 अगस्त, 2019 को लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार नगर पालिका और पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले स्थानीय निकाय चुनाव वर्ष 2018 में हुए थे, जब लद्दाख जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था। स्थानीय निकाय चुनावों के बाद लद्दाख में 4 दिसंबर, 2026 को सभी आठ लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के चुनाव कराने की तैयारी है। चुनाव प्रक्रिया 8 दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है।

मणिपुर में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत, 600 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती



मणिपुरः मणिपुर के चंदेल जिले में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 600 से अधिक लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले दो से तीन दिनों के दौरान शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए। हालांकि, शुरूआत में यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि जहरीली शराब कहां से लाई गई थी और इसकी आपूर्ति किसने की थी।

सुगनू से खरीदी गई थी शराबः पुलिस के मुताबिक, प्रभावित लोगों ने जिस शराब का सेवन किया था, उसे मणिपुर के काकचिंग जिले के सुगनू इलाके से खरीदा गया था। शुरूआती जांच में शराब में मेथनॉल मिलाए जाने की आशंका जताई गई है। इस मामले में अब तक करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार, चंदेल जिले में स्थानीय स्तर पर शराब तैयार किए जाने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐसे में आशंका है कि दूसरे इलाकों से शराब लाकर यहां बेची गई थी। पुलिस अब शराब की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

छह राज्यों में 120 से अधिक मौतेंः गौरतलब है कि वर्ष 2026 में जहरीली शराब के सेवन से मध्य प्रदेश, गुजरात समेत देश के छह राज्यों में 120 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने अवैध शराब की बिक्री और उसकी आपूर्ति पर नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बंधक रखे गए सामान की बिक्री पर धोखाधड़ी का मामला नहीं बनता

झारखंड हाईकोर्ट ने दो कर्जदारों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की रद्द

मेट्रो रेज

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि बैंक के पास बंधक रखी गई वस्तुओं को बैंक द्वारा कर्जदार को सौंपी गई संपत्ति नहीं माना जा सकता। ऐसे में यदि कर्जदार उन वस्तुओं की बिक्री कर देता है तो यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला तभी बनता है, जब लेनदेन की शुरूआत से ही छल या बेईमानी की मंशा हो। ऋण खाते में बाद में होने वाली अनियमितताएं अपने आप में



धोखाधड़ी का आधार नहीं बन सकतीं।

बंधक वस्तुओं का स्वामित्व कर्जदार के पास रहता हैः झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पास बंधक रखे गए स्टॉक की कथित बिक्री से जुड़े मामले में दो कर्जदारों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

पीठ ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह सही मान लेने के बावजूद आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते। मामला याचिकाकर्ताओं द्वारा एसबीआई से ली गई कैश क्रेडिट सुविधा से जुड़ा था। बैंक के अनुसार, बाद में ऋण खाता अनियमित हो गया और सुरक्षा के तौर पर रखा गया स्टॉक निर्धारित स्थान से गायब पाया गया। बैंक ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ताओं और अन्य आरोपियों ने बंधक रखे गए माल को बेच दिया, जिससे विश्वासघात और धोखाधड़ी हुई।

एसबीआई के शाखा प्रबंधक की लिखित शिकायत पर केंदुआडीह थाना कांड संख्या 59/2013 के तहत आईपीसी की धारा 406, 420 और 34 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया और धनबाद के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 26 जून 2025 को मामले में संज्ञान लिया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई बनाम डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले का हवाला देते हुए दलील दी कि बंधक वस्तुओं का स्वामित्व कर्जदार के पास ही रहता है। इसलिए उनकी बिक्री को आपराधिक विश्वासघात नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि ऋण के बदले माल बंधक रखना बैंक द्वारा संपत्ति सौंपने के समान नहीं है।

पांच साल से बिजली बिल जमा नहीं करने पर एचईसी का कनेक्शन कटा, 49 करोड़ रुपये बकाया, उत्पादन ठप

संवाददाता

रांची : राजधानी रांची के धुर्वा स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) की आर्थिक मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पांच साल से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने संस्थान का बिजली कनेक्शन काट दिया है। एचईसी पर बिजली बिल का करीब 49 करोड़ रुपये बकाया है। बिजली आपूर्ति बंद होने से कारखाने में उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है। जानकारी के अनुसार, बिजली बिल का भुगतान करने के लिए विद्युत विभाग की ओर से एचईसी प्रबंधन को कई बार नोटिस और रिमाइंडर भेजे गए थे। विभाग ने बकाया राशि जमा करने के लिए लगातार दबाव बनाया, लेकिन प्रबंधन की ओर से भुगतान नहीं किया गया। पांच साल से बकाया जमा नहीं होने और करीब 49 करोड़ रुपये की राशि लंबित रहने के बाद विभाग ने बिजली कनेक्शन काटने का फैसला लिया।

बिजली आपूर्ति बंद होने का सीधा असर कारखाने के कामकाज पर पड़ा है। बिजली नहीं होने से मशीनें बंद हो गई हैं



और उत्पादन गतिविधियां पूरी तरह रुक गई हैं। पहले से ही आर्थिक संकट, काम की कमी और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे संस्थान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

अब कारखाने में उत्पादन दोबारा शुरू करना प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कभी देश के प्रमुख भारी इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल रहे एचईसी में देश के विभिन्न औद्योगिक और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भारी मशीनों और उपकरणों का निर्माण किया जाता था। लगातार आर्थिक संकट के कारण संस्थान की कार्यक्षमता प्रभावित हुई है। बिजली कनेक्शन कटने के बाद एचईसी के भविष्य और कर्मचारियों की स्थिति को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।

न्यूज IN ब्रीफ

मांडर में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, घर लौटे भाई ने देखा शव

रांची : राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र के मिशन नवाटांड़ में 24 वर्षीय युवती अर्चना कुजूर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय वह घर में अकेली थी। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

जानकारी के अनुसार, घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान अर्चना का छोटा भाई एडविन कुजूर घर लौटा। दरवाजा अंदर से बंद देखकर उसने काफी आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद किसी तरह दरवाजा खोलकर वह घर के अंदर पहुंचा। कमरे में उसने अपनी बहन को रस्सी के सहारे फंदे से लटका पाया। घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। मृतका की पहचान अनिल कुजूर की पुत्री अर्चना कुजूर (24) के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर मांडर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

वादाखिलाफी से दोबारा हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए चालक : संजय सेठ

रांची : रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची के सांसद श्री संजय सेठ ने झारखंड में एंबुलेंस चालकों एवं टेक्नीशियनों की हड़ताल के कारण पूरे राज्य में एंबुलेंस सेवा ठप होने पर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है।

श्री सेठ ने कहा कि पूरे झारखंड में एंबुलेंस सेवा ठप हो चुकी है। यह राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एंबुलेंस जैसी जीवनरक्षक और आपातकालीन सेवा से जुड़े चालकों एवं टेक्नीशियनों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय राज्य सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है, वह उसकी संवेदनहीनता को उजागर करता है। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वास्थ्य मंत्री कर्मचारियों से बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने के बजाय उन्हें ब्लैकमेल करने जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाना अब इस सरकार में अपराध हो गया है?

उन्होंने कहा कि पिछली बार भी जब एंबुलेंस चालक हड़ताल पर गए थे, तब राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने और समाधान निकालने का आश्वासन दिया था। लेकिन सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के बजाय उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज उसी वादाखिलाफी और उपेक्षा का परिणाम है कि एंबुलेंस चालक एवं टेक्नीशियन दोबारा हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर सरकार कब तक आश्वासनों का झुनझुना थमाकर अपनी जिम्मेदारी से बचती रहेगी?

श्री सेठ ने कहा कि इस हड़ताल का सबसे गंभीर और भयावह असर राज्य के लाखों मरीजों पर पड़ रहा है। मरीजों को ई-रिक्शा और ऑटो से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वे निजी एंबुलेंस का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था तक सरकार नहीं कर पा रही है। ऐसे में किसी मरीज की जान चली जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हेमंत सरकार इसकी जवाबदेही स्वीकार करेगी?

उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के दावे किए जाते हैं, वहां जीवन बचाने वाली एंबुलेंस सेवा पूरी तरह ठप है। सरकार की राजनीतिक व्यस्तताएं और प्रशासनिक उदासीनता आम जनता की जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकतीं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को यह समझना होगा कि एंबुलेंस सेवा कोई सामान्य परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में मरीजों के लिए जीवन की उम्मीद होती है।

श्री सेठ ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मांग की कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें। एंबुलेंस चालकों एवं टेक्नीशियनों के प्रतिनिधियों के साथ अविलंब सम्मानजनक वार्ता करें, उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लें और पूरे राज्य में एंबुलेंस सेवा तत्काल बहाल कराएं।

योगी आदित्यनाथ की माता के निधन पर डॉ. प्रदीप वर्मा ने जताया शोक

रांची : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सह प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि सावित्री देवी का निधन अत्यंत दुखद और अपूरणीय क्षति है। मां का स्नेह, त्याग, तपस्या और संस्कार मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। मां का जीवन परिवार के लिए प्रेरणा, ममता और नैतिक मूल्यों का आधार होता है। उनका सानिध्य और आशीर्वाद ऐसी अमूल्य धरोहर है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। डॉ. वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके समस्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति और धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की।

80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी : अजय राय

रांची : झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार पर शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 80 मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलकर अपनी पीठ तो थपथपा ली, लेकिन इन विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति अब तक नहीं की गई है। बिना शिक्षकों के उत्कृष्ट शिक्षा का सपना कैसे पूरा होगा? मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। अजय राय ने कहा कि इन विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना था, लेकिन शिक्षकों की कमी और कमजोर परीक्षा परिणाम सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। वर्ष 2025 में इन विद्यालयों की दसवीं कक्षा का परिणाम 66.34 प्रतिशत और बारहवीं विज्ञान संकाय का परिणाम 61.85 प्रतिशत रहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में शिक्षकों की कमी और खराब शैक्षणिक स्थिति की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री की है। सरकार बताए कि 80 विद्यालयों में कितने शिक्षक पद रिक्त हैं और नियुक्ति कब तक होगी। अजय राय ने मांग की कि रिक्त पदों का विषयवार ब्योरा सार्वजनिक कर नियुक्ति की समयसीमा घोषित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि सुधार नहीं हुआ तो एसोसिएशन राज्यव्यापी आंदोलन करेगा।

10 लाख के इनामी पूर्व माओवादी कमांडर राम प्रसाद लकड़ा को 10 साल की सजा, 80 हजार रुपये जुर्माना

संवाददाता

रांची : झारखंड की जिला एवं अपर सत्र अदालत ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के पूर्व जोनल कमांडर और 10 लाख रुपये के इनामी रहे राम प्रसाद लकड़ा को आर्म्स एक्ट और सीएलए एक्ट के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर कुल 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तीन भूपेश कुमार की अदालत ने सजा सुनाते हुए अपराध की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को प्रमुख आधार माना। सुनवाई के दौरान जेल से वर्चुअल माध्यम से पेश हुए राम प्रसाद लकड़ा ने गरीबी और परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य होने की दलील देते हुए अदालत से राहत की मांग की थी। वहीं, अभियोजन पक्ष ने उसके लंबे



आपराधिक इतिहास और प्रतिबंधित संगठन में महत्वपूर्ण पद पर रहने का हवाला देते हुए कड़ी सजा देने की मांग की।

चार धाराओं के तहत सुनाई गई सजाः अदालत ने राम प्रसाद लकड़ा को आर्म्स एक्ट और सीएलए एक्ट की चार अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार दिया। आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए) और धारा 26(2) सहपठित धारा 35 के तहत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये जुमार्ना लगाया गया। वहीं, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए) सहपठित धारा 35 और सीएलए एक्ट की धारा 17 के तहत तीन-तीन वर्ष की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस कारण दोषी को प्रभावी रूप से 10 वर्ष जेल में बिताने होंगे। उसकी पूर्व न्यायिक हिरासत की अवधि का समायोजन भी सजा में किया जाएगा। जुमार्ना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन ने पेश किए 17 गवाह : मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए कुल 17 गवाह पेश किए। इनमें मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारी, जांच अधिकारी और चिकित्सीय विशेषज्ञ शामिल थे। तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) पवन कुमार सिंह और तत्कालीन थाना प्रभारी धर्मपाल कुमार ने भी गवाही दी। पुलिस ने प्राथमिकी, जब्ती सूची, विशेषज्ञ रिपोर्ट और अभियोजन स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने राम प्रसाद लकड़ा को दोषी ठहराया।

108 एंबुलेंस हड़ताल: वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सम्मान फाउंडेशन को मिली

रांची : राज्य में 108 एंबुलेंस चालकों की हड़ताल और उससे उत्पन्न स्थिति को लेकर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने जिलावार 108 एंबुलेंस की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि प्रत्येक जिले में 108 सेवा से जुड़ी कितनी एंबुलेंस संचालित हैं, सिविल सर्जन कार्यालय के पास कितने वाहन उपलब्ध हैं, कितनी एंबुलेंस बंद हैं और उनके बंद रहने के क्या कारण हैं। उन्होंने यह भी जानकारी ली कि हड़ताल पर गए चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां संबंधित अधिकारियों को सौंप दी हैं या अपने साथ लेकर चले गए हैं। अधिकतर जिलों से जानकारी दी गई कि हड़ताल काफी हद तक प्रभावी है और कई जगहों पर एंबुलेंस चालक वाहन की चाबियां लेकर चले गए हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि जिन चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखी हैं, उनके विरुद्ध सम्मान फाउंडेशन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। प्राथमिकी की प्रतिलिपि विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन जिलों में सभी एंबुलेंस चालक हड़ताल पर हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्मान फाउंडेशन की होगी। यदि फाउंडेशन वैकल्पिक व्यवस्था करने में विफल रहता है तो उसके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन अपने स्तर से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे।

टाटानगर-हावड़ा स्टील एक्सप्रेस की बोगी में लगी आग



इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी गई ट्रेन, टला बड़ा हादसा

रांची : टाटानगर से हावड़ा जा रही स्टील एक्सप्रेस की एक बोगी में चाकुलिया रेलवे स्टेशन के पास अचानक आग लग गई। बोगी से धुआं और आग की लपटें उठती देख यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों के शोर मचाने पर लोको पायलट ने तत्परता दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इससे बड़ा रेल हादसा टल गया।

इलेक्ट्रॉनिक पैनल में शॉर्ट सर्किट की आशंकाः प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रेन के इलेक्ट्रॉनिक पैनल में चूहे के घुसने से शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से आग लगने की बात सामने आई है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच कुछ देर तक दहशत का माहौल बना रहा। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबूः ट्रेन रोके जाने के बाद रेलवे कर्मियों और संबंधित टीम ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग बुझाने में घंटों का समय लगा। घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे अधिकारी जांच में जुट गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पैनल में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। समय रहते लोको पायलट की तत्परता और इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाने से बड़ा हादसा टल गया।

जेल में यौन उत्पीड़न का मामला, मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस

संवाददाता

रांची : राजधानी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में एक युवा विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और शारीरिक प्रताड़ना के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जांच और कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने प्रथम दृष्टया इस घटना को पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना है।

प्रताड़ना और धार्मिक त्योहारों से जुड़ा मामलाः चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने इस संबंध में आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जेल के भीतर कुछ



आपराधिक तत्वों और बंदियों ने पीड़ित को नशीला पदार्थ देकर लगातार यौन उत्पीड़न किया। उसे जबरन महिलाओं के कपड़े पहनाए जाते थे और महाशिवरात्रि, रामनवमी तथा सरहुल जैसे त्योहारों पर हिंदू देवी-देवताओं का रूप धारण करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस दौरान उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट की गई, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आईं और रक्तस्राव हुआ।

जेल अधिकारियों पर अनदेखी का आरोपः शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पीड़ित बंदी ने जब अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार की जानकारी जेल प्रशासन को देने का प्रयास किया, तो अधिकारियों ने उसकी शिकायत पर संज्ञान लेने के बजाय कथित रूप से शिकायत पत्र फाड़ दिया।

जेल अधीक्षक, वार्ड प्रभारी और चिकित्सा पदाधिकारी पर पीड़ित के साथ गाली-गलौज करने तथा उसे प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के आरोप भी लगाए गए हैं। संबंधित अदालत ने 12 जून को पीड़ित को मामले से बरी कर दिया था, लेकिन रिहाई के समय भी उसका समुचित चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया।खेलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज, उच्चस्तरीय जांच की मांगः इस मामले में रांची के खेलगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। शिकायतकर्ता ने आयोग से पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने, बिरसा मुंडा जेल का भौतिक निरीक्षण करने और ऐसे अन्य पीड़ित बंदियों के बयान दर्ज कराने की मांग की है।

इसके अलावा घटना में शामिल आरोपित बंदियों और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। आयोग ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर एचआरसीनेट पोर्टल के माध्यम से जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त

झारखंड पुलिस को जीरो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश

संवाददाता

रांची/नई दिल्ली : झारखंड में लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार को मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करने और अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि लापता व्यक्ति को आखिरी बार झारखंड के देवघर में देखा गया था। ऐसे में राज्य पुलिस को तत्काल मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू करनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने लापता व्यक्ति की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने अपने पति की तलाश के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।

किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है जीरो एफआईआरः सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील से कहा कि राज्य पुलिस इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करे। पीठ ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति को आखिरी बार देवघर में देखा गया था, इसलिए झारखंड पुलिस को



उसकी तलाश के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

जीरो एफआईआर ऐसी प्राथमिकी होती है, जिसे अपराध के घटनास्थल के क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना देश के किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है। बाद में मामले की जांच संबंधित क्षेत्र के थाने को सौंप दी जाती है। इससे शिकायत दर्ज कराने में क्षेत्राधिकार की बाधा नहीं आती।

मेडिकल वीजा पर भारत आया था बांग्लादेशी नागरिकः जानकारी के अनुसार, लापता बांग्लादेशी नागरिक पिछले साल मार्च में मेडिकल वीजा पर भारत आया था। उसे आखिरी बार झारखंड के देवघर में देखा गया था। इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। पति की तलाश में उसकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से स्थिति रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है।

झारखंड सरकार को कार्रवाई की रिपोर्ट देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को लापता व्यक्ति की तलाश के लिए अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा पेश करने को कहा है। अदालत ने राज्य पुलिस को खोजबीन में तेजी लाने और अगली सुनवाई तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद झारखंड पुलिस को जीरो एफआईआर दर्ज कर लापता बांग्लादेशी नागरिक की तलाश के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत के समक्ष रखनी होगी।

झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक

26 आजीवन सजायाफ्ता कैदियों की होगी रिहाई पुनर्वास के लिए काउंसलर नियुक्त करने का निर्देश

मेट्रो रेज

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। इसमें राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में पर्षद की ओर से अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमतिः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ 73



आजीवन सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा की। इस दौरान रिहाई के निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, कैदियों के आचरण, कारावास की अवधि और कानूनी प्रावधानों की समीक्षा की गई। न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट सहित सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

रिहा होने वाले कैदियों के लिए नियुक्त होंगे काउंसलरः मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्षद की अनुशंसा पर रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास के लिए विभाग की ओर से काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जेल से बाहर आने के बाद बंदी दोबारा किसी अपराध में शामिल न हों।

रिहा हुए कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त करने के साथ गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया गया। मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के बेहतर इलाज की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर (पीओ) को सौंपने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि सजा पूरी करने के बावजूद जेल से बाहर नहीं निकलना चाहने वाले कैदियों की काउंसलिंग कराई जाए। उनके जेल से बाहर नहीं आने के कारणों का पता लगाने के साथ पारिवारिक स्थिति की जानकारी भी ली जाए।

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

लुगू बुरु राजकीय महोत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रण

22 से 24 नवंबर तक ललपनिया में होगा तीन दिवसीय महोत्सव
आयोजन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

मेट्रो रेज

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में लुगू बुरु घांटाबाड़ी धोरोमगढ़ राजकीय महोत्सव-2026 की आयोजन समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना भी मौजूद रहे।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी 22 से 24 नवंबर 2026 तक बोकारो के टीटीपीएस, ललपनिया में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय लुगू बुरु घांटाबाड़ी धोरोमगढ़ राजकीय महोत्सव में शामिल होने के लिए सादर



आमंत्रित किया।

इस अवसर पर उपायुक्त अजय नाथ झा ने मुख्यमंत्री को महोत्सव के आयोजन से संबंधित तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति को शुभकामनाएं दीं। मौके पर अंतरराष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन आयोजन समिति के अध्यक्ष बबुली सोरेन और सदस्य लुदू मांझी भी उपस्थित थे।

यूजी सेमेस्टर-8 की परीक्षा के लिए 25 नवंबर से भरे जाएंगे फॉर्म

30 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क आवेदन का मौका, दिसंबर से जनवरी के बीच परीक्षा की तैयारी



संवाददाता

रांचीः रांची विश्वविद्यालय ने नयी शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत शुरू किए गए चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के पहले बैच के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर-8 (रेगुलर) की परीक्षा का फॉर्म भरने की अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र 2022-26 के विद्यार्थी 25 से 30 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे।

1 से 4 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदनः निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों को 1 से 4 दिसंबर के बीच विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा। इसके लिए 400 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।

परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्कः विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विभिन्न शुल्क निर्धारित किए हैं। इसके तहत परीक्षा शुल्क 300 रुपये, लोकल लेवी 250 रुपये, मार्कशीट शुल्क 50 रुपये और अतिरिक्त प्रैक्टिकल शुल्क 100 रुपये देना होगा। दिसंबर-जनवरी में हो सकती है परीक्षाः विश्वविद्यालय सत्र को नियमित करने की दिशा में सेमेस्टर-8 की परीक्षा दिसंबर और जनवरी के बीच आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, परीक्षा की अंतिम तिथि को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम जारी होना बाकी है। इस परीक्षा के साथ ही नयी शिक्षा नीति के तहत शुरू हुए चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के पहले बैच का अंतिम सेमेस्टर पूरा हो जाएगा।

मौलाना आजाद कॉलेज ने मौलाना सज्जाद नोमानी को किया सम्मानित

मौलाना आजाद की 138वीं जयंती पर शिक्षा, सामाजिक सुधार और समाजसेवा में योगदान को किया याद



गुलाम शाहिद

रांचीः देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद् एवं आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की 138वीं जयंती के अवसर पर मौलाना आजाद कॉलेज, रांची की ओर से विश्व प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान, चिंतक एवं शिक्षाविद् हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी को सम्मानित किया गया। कॉलेज के अध्यक्ष हाजी मोखतार अहमद और प्रोफेसर मौलाना उबैद उल्लाह कासमी ने रांची स्थित हज हाउस में उनसे मुलाकात कर सम्मान प्रदान किया। मौलाना सज्जाद नोमानी एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए रांची पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें शिक्षा, सामाजिक सुधार, दीन की खिदमत और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर कॉलेज के अध्यक्ष हाजी मोखतार अहमद ने कहा कि मौलाना सज्जाद नोमानी से मुलाकात के दौरान विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक विषयों पर विचार साझा करने का अवसर मिला। उनका व्यापक अनुभव, ज्ञान और दूरदर्शी सोच समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद की जयंती पर ऐसी शख्सियत को सम्मानित करना गौरव की बात है, जिन्होंने शिक्षा, समाज और दीन की खिदमत के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। यह मुलाकात शिक्षा, सामाजिक चेतना और विचारों के आदान-प्रदान के लिहाज से महत्वपूर्ण रही।

प्रतिबंधित जमीनों की सूची तैयार करेगा नगर निगम, अतिक्रमण हटाने की भी तैयारी



रांचीः रांची नगर निगम शहर में प्रतिबंधित जमीनों की सूची तैयार करेगा। साथ ही, अधिग्रहित और नगर निगम को गिफ्ट डीड के माध्यम से मिली जमीनों को चिह्नित कर अतिक्रमणमुक्त कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

इस संबंध में नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में भू-संपदा शाखा और डीसीएलआर के साथ बैठक हुई। बैठक में नगर आयुक्त ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए अब तक अधिग्रहित की गई जमीनों का पूरा ब्योरा नगर निगम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने भूमि अधिग्रहण से संबंधित अभिलेख जुटाने को कहा, ताकि जमीन की वर्तमान स्थिति और उपयोगिता का आकलन किया जा सके।

प्रतिबंधित जमीनों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देशः बैठक में जानकारी दी गई कि नगर निगम के पास प्रतिबंधित खरीद-बिक्री वाली जमीनों की सूची उपलब्ध नहीं है। इस पर नगर आयुक्त ने एलआरडीसी को ऐसी जमीनों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि प्रतिबंधित भूमि का पूरा ब्योरा निगम के पास उपलब्ध हो सके।

अधिग्रहित जमीनों को अतिक्रमणमुक्त कराने पर जोरः नगर आयुक्त ने अधिग्रहित और गिफ्ट डीड के माध्यम से नगर निगम को मिली जमीनों को चिह्नित कर अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्देश दिया। इसके लिए संबंधित जमीनों के अभिलेख जुटाने और उनकी मौजूदा स्थिति की जानकारी लेने को कहा गया। उन्होंने जमीनों का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

आड्रे हाउस में 22 नवंबर को सजेगी सुरों की महफिल, *श्रजन द स्पार्क* के कलाकार बिखेरेंगे संगीत का जादू

मेट्रो रेज



रांचीः राजधानी में 22 नवंबर, रविवार को शाम 6 बजे से आड्रे हाउस में संगीत की शानदार महफिल सजेगी। श्रजन द स्पार्क के रांची चैप्टर की ओर से आयोजित इस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में संस्था के सदस्य अपनी गायन और संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति होगी, जो संगीत प्रेमियों के लिए यादगार अनुभव साबित होगी। कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले अधिकांश कलाकार पेशेवर गायक नहीं हैं, बल्कि समाज और प्रशासन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं या वर्तमान में कार्यरत हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले इन प्रतिभाशाली लोगों के दिलों में संगीत के प्रति गहरा लगाव है। यह आयोजन साबित करेगा कि प्रतिभा किसी पेशे या पद की मोहताज नहीं होती। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मुकेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। आयोजन की तैयारियां ह्यश्रजन द स्पार्कह्ण रांची चैप्टर के अध्यक्ष अरशद उबैद, सचिव सागरिका सरकार (वीणा श्री), मुख्य संरक्षक एवं सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त डीआईजी डीएन लाल, अतुल्य कुमार वर्मा और उपाध्यक्ष उपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में की जा रही हैं। कार्यक्रम का संचालन उद्घोषिका अंकिता केडिया करेंगी। इस मौके पर इवेंट मैनेजर वसीम आलम भी मौजूद रहेंगे।

एकादशी पर खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मना, मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

मेट्रो रेज

रांचीः हरमू रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर में एकादशी के अवसर पर खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास और भक्तिमय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया और आकर्षक सजावट की गई। साथ ही विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन हुआ।

मंदिर के पुजारी शिव दुबे ने बताया कि बाबा के जन्मोत्सव पर उन्हें विशेष प्रसाद अर्पित किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच व्यापक रूप से प्रसाद का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन जन्मोत्सव के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और बाबा के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा।



Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, Ramgarh

SHORT TENDER NOTICE

Tender Notice No: 1516/DHS/ 2026 Dated 20/11/2026

Civil Surgeon-Cum-CMO, Ramgarh invites Tender under NHM for Empanelment from eligible Ultrasound Clinic/Diagnostic Centers having valid license and experience for diagnostics.

Sl	Particulars	Details
1	Name of the work	Empanelment of USG Clinics
2	Date of Publication of Tender	Dt. 21/11/2026
3	Date of Pre-bid Meeting	Dt. 25/11/2026
4	Last date of receipt of Bids	Dt. 07/12/2026 by 5pm
5	Tender Fee 1000/- EMD of Rs. 20,000/-	In the name of DRHS RCH Flexible Program
6	Date and Time of Bid opening	Dt. 08/12/2026 on 01.30PM
7	Contact Number	9431390128/7979928513

Note:-Please contact CS Office(PMU) for tender documents.

Sd/-
Civil Surgeon-cum-CMO Ramgarh,

PR.NO.394303 Health Med Edu and Family Welfare(26-27):D

108 एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर छह महीने तक एस्मा लगाने की तैयारी

स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, मंत्री की मंजूरी के बाद गृह विभाग को भेजी जाएगी फाइल

संवाददाता

,4,बॉटम

रांचीः झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। 18 नवंबर की रात से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे असर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एस्मा लगाने की तैयारी कर रहा है।

विभाग ने छह महीने तक एस्मा लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे संबंधित फाइल स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी



को भेजी गई है। मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए गृह विभाग को भेजा जाएगा।

छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध की तैयारीः सरकार का मानना है कि एंबुलेंस सेवा बाधित रहने से गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में परेशानी हो सकती है। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए विभाग आपातकालीन सेवा को हर हाल में चालू रखना चाहता है। स्वास्थ्य विभाग की योजना वैकल्पिक व्यवस्था पूरी तरह लागू होने तक छह महीने के लिए एस्मा लागू करने की है। इसके लागू होने पर 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल पर कानूनी रोक लगाई जा सकेगी।

20 कर्मचारियों की पहचान, कार्रवाई की तैयारीः स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी सम्मान फाउंडेशन के साथ मिलकर 20 कर्मचारियों को चिह्नित किया है। इन कर्मचारियों पर जानबूझकर एंबुलेंस सेवा बाधित करने में भूमिका निभाने का आरोप है। संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

क्या है एस्मा? : एस्मा यानी आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत सरकार जनहित से जुड़ी जरूरी सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर एस्मा लागू होने के बाद संबंधित कर्मचारियों के लिए हड़ताल जारी रखना गैरकानूनी हो सकता है। सरकारी आदेश की अवहेलना करने, हड़ताल जारी रखने या इसके लिए उकसाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें जुर्माना और कारावास जैसी सजा हो सकती है। हालांकि, झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों पर एस्मा लागू करने का प्रस्ताव अभी मंजूरी की प्रक्रिया में है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
न्यायालयः-प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल

सूचना

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल के प्रशासनिक क्षेत्राधीन भारतीय वन अधिनियम, 1927 (संपठित बिहार संशोधन, 1989) के सुसंगत प्रावधानों के उल्लंघन करने के विरूद्ध जप्त वनोपज एवं वाहन पर प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल के न्यायालय में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (संपठित बिहार संशोधन, 1989) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के तहत् राज्यसात की कार्रवाई चल रही है, जिसमें संबंधित पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित **सुनवाई की तिथि 05.12.2026** को प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें, अन्यथा न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकतरफा निर्णय ले लिया जायेगा। जप्त वनोपज एवं वाहन तथा वन वाद से संबंधित अधिहरण वाद की विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	अधिहरण वाद संख्या	जप्त वन पदार्थ की विवरणी	प्रतिपक्ष का नाम एवं पता
01	23/2025	खैर लकड़ी बोटा (314 पीस– 6.4573 घन मी0) तथा ट्रक मॉडल **TATA LPT3118TC,** चेचीस नं0 **MAT466441F5J12751,** इंजन नं0 **51J84251822,Reg.No.- HR 46D - 7092**	1. वाजिद, पिता– लतीफ, ग्राम– इब्राहिमपुर, तहसील– छछरौली, जिला– यमुनानगर, राज्य– हरियाणा, पिन– 135103

प्राधिकृत पदाधिकारी,
–सह–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल

PR 394255 Forest, Environment and Climate Changes(26-27).D

सूक्ति

सबसे प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो
अन्याय किसी के साथ मत करो : शेक्सपियर

अश्लीलता की लीला

इसमें दो राय नहीं कि सोशल मीडिया समाज में सहज-सरल संवाद व मुखर अभिव्यक्ति का माध्यम बना है। लेकिन इसमें संपादक नामक संस्था न होने के कारण यह माध्यम धीरे-धीरे अराजक सामग्री, हिंसक अभिव्यक्ति और अश्लीलता का प्रसारक व पोषक बनता जा रहा है। दरअसल, इन कंपनियों का प्रारूप कुछ इस तरह बनाया गया है कि सामाजिक मयार्दाओं का अतिक्रमण करने वाली और बच्चों के मन-मस्तिष्क पर बुरा असर डालने वाली सामग्री दर्शकों का ध्यान ज्यादा खींचती है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया माध्यमों पर बच्चों के यौन-शोषण से जुड़ी सामग्री के विज्ञापनों के प्रसारण को लेकर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया था। बाकायदा मेटा को इस बाबत नोटिस भी दिया गया था। तब भी इन कंपनियों की जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगे थे। विडंबना ही है कि हिंसक, अश्लील व सनसनी फैलाने वाली सामग्री को दर्शकों की ज्यादा प्रतिक्रिया मिलती है, जो इन कंपनियों के अर्थशास्त्र का आधार भी है। विडंबना यह भी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का एल्गोरिद्म उपयोगकताओं की अभिरुचि और प्रतिक्रिया के चलते ऐसी सामग्री का अधिक प्रसार करने लगता है। अब सरकार की प्रतिक्रिया व कुछ प्रबुद्ध लोगों के प्रतिरोध के बाद इंस्टाग्राम ने अपने कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम में बदलाव लाने की बात कही है। इसके अंतर्गत दावा किया जा रहा है कि एआई की मदद से अश्लील व हिंसक सामग्री की संस्तुति को उपयोगकताओं तक पहुंचने से पहले ही हटाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी सामग्री को बढ़ावा देने में कंपनी की कोई भूमिका होती है? यदि नहीं, तो इसे कौन बढ़ावा देता है? सवाल यह भी है कि प्लेटफॉर्म पर सामग्री की निगरानी करने वाला एल्गोरिद्म भारतीय परिवेश में वर्जित सामग्री को लेकर अपेक्षित संवेदनशीलता दिखा पाएगा? बहुत संभव है कि सोशल मीडिया पर सूचनाओं व कार्यक्रमों का स्वरूप निर्धारित करने में पश्चिमी समाज का दृष्टिकोण प्रभावी होता हो। तो क्या एआई आधारित निगरानी व्यवस्था समस्या का संपूर्ण समाधान दे पाएगी?

वास्तव में इस बात की संभावना कम ही नजर आती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्टरिंग व्यवस्था सोशल मीडिया पर अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री पर पूरी तरह नियंत्रण लगा सकेगी। मशीन मानवीय अहसासों को पूरी तरह नहीं समझ सकती। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मानवीय निगरानी और शिकायतों के शीघ्र निस्तारण का तंत्र भी बने। अब तो जो पश्चिमी देश कल तक सोशल मीडिया का गुणगान करते नहीं अघाते थे, वे भी इससे बच्चों में पनपती विकृतियों की हकीकत समझने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्कॉटलैंड आदि देशों ने एक निर्धारित उम्र के किशोरों की सोशल मीडिया तक पहुंच पर रोक लगाई है। न्यू मेक्सिको में एक जूरी ने मेटा को इस बात के लिए जवाबदेह ठहराया कि उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वयस्क सामग्री तक बच्चों की पहुंच बनी हुई है, जिससे उनके जीवन में यौन अपराधियों से खतरा बढ़ गया है। लेकिन भारत जैसे देशों में सोशल मीडिया के बच्चों के जीवन पर घातक प्रभावों के बावजूद नियामक कानून न होने से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। मांग की जा रही है कि एक निर्धारित आयु से अधिक उम्र के बच्चे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच बना सकें। विडंबना यह भी है कि बच्चों को संस्कार अब माता-पिता व शिक्षक नहीं, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का दोहन करने वाले स्वार्थी तत्व दे रहे हैं, जो भारतीय जीवन-मूल्यों व संस्कारों से मेल नहीं खाते। आज सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इतनी अश्लील व द्विअर्थी सामग्री का प्रवाह है कि हमारे किशोर आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों के चलते आज बच्चों के नायक व आदर्श बदल गए हैं। उनका नजरिया बदल रहा है। अश्लील सामग्री की उपलब्धता ने ब्रह्मचर्य के भारतीय दर्शन को ताक पर रख दिया है। इसका प्रभाव बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन व एकाग्रता पर भी पड़ेगा। दुखद है कि बच्चे इंटरनेट पर उपलब्ध अश्लील सामग्री से अपरिपक्व उम्र में रूबरू हो रहे हैं। फलतः अल्पवयस्कों में यौन अपराधों की वृद्धि घातक स्तर तक पहुंच रही है। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए घर और स्कूल में बच्चों को सोशल मीडिया के स्याह पहलुओं से अवगत कराना जरूरी है।

जेलों का मानवीय चेहरा

निश्चित रूप से, मानव सभ्यता में जब कभी भी जेलों की शुरूआत हुई होगी, उसका मकसद भूले-भटके लोगों में सुधार करना ही रहा होगा। ताकि समाज से अलग-थलग रहकर अभियुक्त व अपराधी को आत्ममंथन करने का मौका मिल सके। जिससे वो अपने व्यवहार में सुधार ला सके। निस्संदेह, जेल की सजा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सकती है, न कि उसकी गरिमा या संवैधानिक अधिकार। राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह हिरासत में बंद लोगों के हितों का ध्यान रखे। लेकिन अक्सर जेलों में निर्धारित संख्या से अत्यधिक भीड़, लंबे समय तक विचाराधीन बंदियों का कैद में रहना, हिरासत में दुर्व्यवहार, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और खराब पुनर्वास व्यवस्था की शिकायतें मिलती हैं। जिनके प्रति जेल प्रशासन व शासन द्वारा संवेदनशील रवैया अपनाया जाना चाहिए। ऐसे में हरियाणा सरकार की उस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत सभी बीस जेलों के लिये ह्यबोर्ड ऑफ विजिटर्सह्न गठित करने का फैसला लिया गया है। निस्संदेह, यह प्रयास जेल प्रशासन को अधिक जवाबदेह व मानवीय बनाने की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। दरअसल, यह कदम सुप्रीम कोर्ट के अक्तूबर 2024 के उस ऐतिहासिक फैसले के आलोक में ही उठाया गया है, जिसमें कोर्ट ने जेलों के भीतर जाति-आधारित भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया था। अदालत ने जेल की दीवारों के पीछे मौजूद सामाजिक ऊंच-नीच की चिंताजनक स्थिति को उजागर किया था। जहां समाज में हाशिये पर रहने वाले समुदायों के कैदियों को छोटे-मोटे और निम्न स्तर के काम सौंपे जाते थे। इस तरह उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा। सही मायने में इस नई पहल को केवल अदालती आदेश के पालन करने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ह्यमॉडल प्रिजन मैनुअल-2016ह्न और हरियाणा के अपने ह्यप्रिजन रूल्स-2022ह्न में पहले से ही ऐसी निगरानी प्रणाली का प्रावधान रहा है। इसके बावजूद राज्यों को इन्हें लागू करने के लिये प्रेरित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा है। निस्संदेह, हरियाणा द्वारा राज्य की सभी जेलों के लिये ह्यबोर्ड ऑफ विजिटर्सह्न गठित करने के कदम के सकारात्मक परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। इसी क्रम में जिला-स्तरीय बोर्डों का गठन किया जा सकता है। जिसमें जिला मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में प्रशासन,पुलिस,स्वास्थ्य सेवाओं, निर्वाचित प्रतिनिधि और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। इससे जेलों के भीतरी प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यक जांच-पड़ताल हो सकेगी। इसके अंतर्गत हर तीन महीने में जेलों का निरीक्षण करने, कैदियों तक बिना किसी बाधा के पहुंच बनाने और बंदियों के रहन-सहन,स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पुनर्वास के इंतजामों की जांच करना प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे सार्थक प्रयास करने से व्यवस्था की खामियां उजागर हो सकती हैं। लेकिन वास्तव में यह कवायद तभी सार्थक होगी, जब बोर्ड के सदस्यों को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट मिल सके।

समुद्री मार्गों को सुचारु रखने में भारत की भूमिका

जब कोई एक समुद्री मार्ग बंद हो जाए, तो युद्धस्थल से बहुत दूर तक भी उसका असर होता है। ऐसे में कोई मालवाहक जहाज वहां से नहीं गुजर पाता। केरल का कोई परिवार खाड़ी देशों से आने वाले धनार्जन के इंतजार में होता है। किसान के लिए डीजल और खाद महंगे हो जाते हैं। बीमा प्रीमियम बढ़ते हैं, और जिन देशों का उस विवाद से लेना-देना नहीं, उन्हें भी उसका बोझ उठाना पड़ता है। ऐसे में ह्यडिटरेंसह्न (दुश्मन को भयाक्रांत कर हतोत्साहित करने की क्षमता) मायने रखती है; वहीं स्पष्ट नियम, समय पूर्व जानकारी साझा करना और सेवाओं को तेजी से बहाल करने की क्षमता भी जरूरी है।

रवि कुमार

हर सैनिक यह सीखता है कि कोई जमीन या इलाका कभी तटस्थ नहीं रह सकते। एक पुल या पहाड़ी दर्रा किसी लड़ाई का नतीजा तय कर सकता है। समुद्र में, ह्यस्ट्रेट्सह्न (संकरे समुद्री मार्ग) की अहमियत भी उतनी ही है। इन मार्गों को सुरक्षित करके व्यापार को निरापद बनाया जा सकता है, दुश्मन पर दबाव डालने के काम आ सकते हैं या किसी लड़ाई की दिशा बदल सकते हैं।

इतिहास में इसकी भारी कीमत दर्ज है। 1915 में गैलीपोली में भारतीय सैनिकों ने ऐसे अभियान में हिस्सा लिया था, जो अंततः बड़ी विफलता सिद्ध हुआ। आज, जब होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव व्याप्त है और बाब अल-मंदेब के पास हमले हो रहे हैं, तो भारतीय नौसैन्य युद्धपोत व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता पार कराने में मदद कर रहे हैं। एक जगह बनी बाधा का असर दूर तक फैलता है। ह्यचोकपॉइंटह्न का मतलब अब सिर्फ वह समुद्री रास्ता नहीं रहा जिस पर युद्धपोत नजर रखते हैं। इसमें समुद्र तल पर डली डेटा केबल, ईंधन ढुलाई जलमार्ग, अथवा भोजन एवं दवा आपूर्ति शृंखला भी शामिल है। कोविड-19, जलवायु परिवर्तन और युद्धों ने दर्शाया है कि दुनिया के एक भाग में रुकावट कैसे दूसरे कोने के लोगों की आजीविका प्रभावित करती है। अब इसमें एक चौथा ह्यसीह्न अवयव भी जुड़ गया है : चोक पॉइंट्स का इस्तेमाल हथियार के रूप में करना। जिन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, अक्सर उन्हीं की बात सबसे कम सुनी जाती है। नेटवर्क टूटने में किसी का फायदा नहीं।

जब कोई एक समुद्री मार्ग बंद हो जाए, तो युद्धस्थल से बहुत दूर तक भी उसका असर होता है। ऐसे में कोई मालवाहक जहाज वहां से नहीं गुजर पाता। केरल का कोई परिवार खाड़ी देशों से आने वाले धनार्जन के इंतजार में होता है। किसान के लिए डीजल और खाद महंगे हो जाते हैं। बीमा प्रीमियम बढ़ते हैं, और जिन देशों का उस विवाद से लेना-देना नहीं, उन्हें भी उसका बोझ उठाना पड़ता है। ऐसे में ह्यडिटरेंसह्न (दुश्मन को भयाक्रांत कर हतोत्साहित करने की क्षमता) मायने रखती है; वहीं स्पष्ट नियम, समय पूर्व जानकारी साझा करना और सेवाओं को तेजी से बहाल करने की क्षमता भी जरूरी है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति से भारत का सीधा हित एवं विशेष ज़िम्मेदारी जुड़ी है। हिंद महासागर जलराशि पश्चिम में होर्मुज और बाब अल-मंदेब को पूर्व में मलक्का जलडमरूमध्य से जोड़ती है। भारत की समृद्धि उन समुद्री रास्तों पर निर्भर है जो खुले रहें और जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सके। भारत की केंद्रीय स्थिति सहयोग का आधार बन सकती है, न कि अड़ंगा डालने का जरिया। हिंद महासागर किसी एक देश की जागीर नहीं। इसके समुद्री रास्तों पर पूर्वी अफ्रीका से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक की अर्थव्यवस्थाएं टिकी हैं, इसलिए इन रास्तों तक मुक्त पहुंच कायम रखने में जो हित भारत का है, वही कई अन्य देशों का भी है। विभक्त विश्व में रणनीतिक स्वायत्तता : रणनीतिक स्वायत्तता का उद्देश्य भारत को कार्रवाई करने की अपनी आजादी से कहीं अधिक हो। विभक्त विश्व में, भारत का आकार और विदेशी क्षेत्रीय प्रभुत्व से बचे रहने का उसका इतिहास अशांति को शांति में बदलने का मौका देता है। विश्वास आचरण के जरिए अर्जित होता है, खासकर छोटे पड़ोसियों के प्रति व आपदा राहत कार्यों में शीघ्र मदद से। भारत के पास अगुवाई कर सार्थकता बनाने का अनुभव है। भारतीय सैनिकों ने दशकों तक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा में सेवा दी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सह-स्थापन और आपदा प्रबंधन अवसंरचना गठबंधन की शुरूआत की। ह्यवैक्सीन मैत्रीह्न ने छोटे द्वीपीय देशों समेत दुनियाभर में इसकी डोज भेजीं। ह्यहॉर्न ऑफ अफ्रीकाह्न तट पर समुद्री डाकू प्रतिरोधक भारतीय गश्ती दलों ने कई देशों के जहाजों को सुरक्षा दी। ये ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाना एक जरूरत है। निगरानी, सुरक्षा और बचाव करने में सक्षम नौसेना अपने हित सुरक्षित करते हुए, व्यापार मार्ग सुचारु रखती है। अगुवाई कोई निष्क्रिय काम नहीं : यह विश्वसनीय क्षमता की मांग करती है। भारत को निरापद समुद्री मार्ग और डिजिटल लोचशील तंत्र स्थापित करना होगा, वह जो व्यवधानों की रोकथाम करे और साझा मार्गों को दबाव बनाने का जरिया बनाने से रोके। सुरक्षा अंततः लोगों से जुड़ी है, और उनकी आजीविका समुद्री मार्ग से माल ढुलाई, टैंकरों द्वारा आने वाले ईंधन और केबलों से संचारित डेटा पर निर्भर करती है। यही चीज मानवता को साझा वैश्विक संसाधन के रूप में मानने का अर्थ है। यह कोई कानूनी श्रेणी अथवा स्वामित्व का दावा नहीं, व्यावहारिक सिद्धांत है। पहुंच मार्गों की सुरक्षा करना, व्यवधान कम करना और पुनर्स्थापन को संभव बनाना। कसौटी सरल है। क्या कोई कार्रवाई उन लोगों के लिए साझा मार्गों को खुला रख सकती है, जिन्होंने यह संकट नहीं चुना? सिद्धांत से व्यवहार तक : प्रथम, उन धमनियों की सुरक्षा करना जिन पर किसी की नजर नहीं पड़ती। जैसे, समुद्र तल पर बिछी डेटा केबल, लैंडिंग स्टेशन व मरम्मत क्षमता पर भी उतना ही ध्यान दें, जितना हम जहाजरानी मार्ग व बंदरगाहों पर देते हैं। 2025 में जेद्दा के पास डेटा केबल खराब होने से भारत, पाकिस्तान और खाड़ी देशों में संचार कनेक्टिविटी प्रभावित हुई थी। हमें बेहतर निगरानी, त्वरित मंजूरी और मरम्मत क्षमता रखनी चाहिए। द्वितीय, तटीय राष्ट्रों को इस काम में साथ जोड़ना। जब उनके समुद्री क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो पहले असर उन तटीय राष्ट्रों पर पड़ता है। इसलिए, उनके लिए नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर क्षेत्रीय ढांचे तैयार किए जाएं। ह्यकोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेवह्न और ह्यइंडियन ओशन रिम एसोसिएशनह्न इसके शुरूआत बिंदु हैं; तटीय राष्ट्रों के साथ सतत परामर्श व भारत के सूचना-साझाकरण नेटवर्क से उन्हें मजबूती मिलेगी। तृतीय, संकट आने से पहले ही भरोसा कायम करना। गुरुग्राम स्थित हिंद महासागर क्षेत्र सूचना आदान-प्रदान केंद्र में तटीय राष्ट्रों के संपर्क अधिकारी मौजूद हैं। इसका नेटवर्क जहाजरानी कंपनियों, बीमा कंपनियों और केबल ऑपरेटरों तक होना चाहिए, जिसके लिए प्रोटोकॉल तय हो। चतुर्थ, समुद्री क्षेत्र सैन्य कार्रवाई कमान का दायरा हिंद महासागर तक फैलाना। नौसेना पहले ही इस दिशा में कार्यरत है। साल 2023 के अंत से, इसने अरब सागर और अदन की खाड़ी से आए आपात-संदेशों पर त्वरित कार्रवाई की, चालक दल बचाए व व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा दी।

विश्व कूटनीति की दिशा बदलेगी शेन्झेन बैठक!

मनीला में आयोजित 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकों को लेकर चीन की असहजता के पीछे कई प्रमुख कूटनीतिक कारण थे। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले अक्तूबर 2026 में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन ने फिलीपींस पर जानबूझकर बाधाएं खड़ी करने और राजनयिक प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया था। इसके विरोध में चीन ने अपने रक्षा मंत्री के बजाय एक निचले स्तर के सैन्य प्रतिनिधि (डिफेंस अताशे) को भेजा था। तीखी टिप्पणियों से नाराज पेइचिंग ने फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो तियोदोरो की चीन यात्रा पर प्रतिबंध भी लगाया था। चीनी राष्ट्रपति शी इन वजहों से मनीला बैठक में नहीं आये। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग ने चीन का प्रतिनिधित्व किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में भाग लेने गए थे। भले ही भारत आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन यह संगठन के साथ साझेदारी और संवाद तंत्र के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आसियान की मशाल अब सिंगापुर के हाथों में है। वर्ष 1967 में स्थापित आसियान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर-लेस्ते शामिल हैं। वर्ष 2027 में इस क्षेत्रीय समूह की 60वीं वर्षगांठ होगी।

लेकिन, पीएम मोदी का मनीला जाना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि वहां क्वाड समूह की शिखर बैठक भी साथ-साथ निपट गई। क्वाड में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। मंगलवार को क्वाड नेता फिलीपींस की राजधानी मनीला में बगलगीर थे। सितंबर 2024 के बाद से यह उनकी पहली मुलाकात थी। चीनी पर्यवेक्षक इससे चिढ़ से गए. ह्यग्लोबल टाइम्सह्न ने उनके हवाले से तंज किया, ह्ययह समूह फोटो डिप्लोमेसी तक ही सीमित है। जिसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता।ह्न

मनीला में आयोजित 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकों को लेकर चीन की असहजता के पीछे कई प्रमुख कूटनीतिक कारण थे। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले अक्तूबर 2026 में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन ने फिलीपींस पर जानबूझकर बाधाएं खड़ी करने और राजनयिक प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया था। इसके विरोध में चीन ने अपने रक्षा मंत्री के बजाय एक निचले स्तर के सैन्य प्रतिनिधि (डिफेंस अताशे) को भेजा था। तीखी टिप्पणियों से नाराज पेइचिंग ने फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो तियोदोरो की चीन यात्रा पर प्रतिबंध भी लगाया था। चीनी राष्ट्रपति शी इन वजहों से मनीला बैठक में नहीं आये। उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग ने चीन का प्रतिनिधित्व किया।

वजह साऊथ चाइना सी है, जहां चीन के अलावा फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान इस क्षेत्र के अलग-अलग द्वीपों और जलक्षेत्रों पर अपना दावा जताते रहे हैं। इंडोनेशिया के साथ भी उसके समुद्री क्षेत्र को लेकर मतभेद हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने 2016 में फिलीपींस के पक्ष में फैसला देते हुए चीन के ऐतिहासिक दावों को अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध बताया था, लेकिन चीन इस फैसले को नहीं मानता है।

मनीला शिखर बैठक में दक्षिण चीन सागर की आचार संहिता पर आसियान देश और चीन अंतिम समझौते तक नहीं पहुंच सके, हालांकि मसौदे के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से पर अस्थायी सहमति बन चुकी थी। अब शायद सिंगापुर शिखर बैठक में कुछ हो। फिलीपींस ने अपनी आसियान अध्यक्षता के दौरान 2026 के अंत तक इस समझौते को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन मतभेदों के कारण यह पूरा नहीं हो सका। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक बिलाहारी कौसिकन अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर हैं। 2015 में सिंगापुर में आयोजित एक सम्मेलन में बिलाहारी ने आसियान की तुलना ह्यएक गायह्न से की थी, जो ह्यकभी घोड़ा नहीं बन सकती।ह्न उन्होंने कहा कि दोनों ही जानवर उपयोगी हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता का स्तर अलग-अलग है।

लेकिन, मनीला शिखर बैठक से बड़ी कूटनीतिक कहानी शेन्झेन शिफ्ट कर गई है, जहां दुनिया के तमाम देशों की निगाहें पुतिन, ट्रम्प और शी की त्रिपक्षीय मुलाकात पर है। 18 से 19 नवंबर 2026 को 21 सदस्यीय एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन चीन के शेन्झेन शहर में आयोजित हो रहा है। 19 नवंबर को शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली मुलाकात में विश्व की दिशा बदलेगी, ऐसा अनुमान कुछ पर्यवेक्षक लगा रहे हैं। ह्ययेपेकह्न पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है।

समुद्री मार्गों को सुचारु रखने में भारत की भूमिका' : अगरचे, यह त्रिपक्षीय बैठक ट्रंप के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी की शर्मनाक हार की पृष्ठभूमि में हो रही है, इसलिए ट्रंप इसमें अपने लिए एक ही फायदा देखते हैं - जो जरूरी नहीं कि अमेरिका के लिए भी फायदेमंद हो। वह अपने घरेलू समर्थकों के सामने यह दावा कर सकते हैं कि मध्यावधि चुनावों में हार के बावजूद, ह्ययह अभी भी इतने ताकतवर हैं कि दुनिया चला सकते हैं।

लेकिन, ट्रम्प की छवि की जिस तरह मिट्टी पलीद हुई है, ट्रम्प की ऐसी दावेदारी को शायद ही कोई सीरियसली ले। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के चाइना सेंटर के फेलो जोनाथन ए. ज़िन का कहना है कि ऐसी किसी स्थिति की कल्पना करना मुश्किल है, जिसमें ट्रंप, शी और पुतिन के बीच होने वाली बैठक से अमेरिका और उसके हितों के लिए कोई अच्छा नतीजा निकले।

हालांकि, शेन्झेन में त्रिपक्षीय बैठक पुतिन की हामी के बाद ही तय हुई है। इस साल मई में राष्ट्रपति ट्रंप की पेइचिंग यात्रा के बाद से ही शी-ट्रंप-पुतिन के बीच एक संभावित त्रिपक्षीय बैठक को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। जैसे ही ट्रंप ने पुष्टि की कि वह शेन्झेन में होने वाले एपेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, पुतिन ने बिना समय गंवाए 9 अक्तूबर को फोन पर बातचीत के दौरान अपने अमेरिकी समकक्ष के सामने एक संयुक्त बैठक का प्रस्ताव रख दिया। यूक्रेन पर रूस के पूर्ण सैन्य आक्रमण के बाद से उन्हें वर्षों तक कूटनीतिक अलगाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ा था।

ट्रम्प के तेवर भी मध्यावधि चुनाव परिणाम के बाद से ढीले लग रहे हैं। मनीला में पीएम मोदी के साथ उनकी देहभाषा दोस्ताना थी। मनीला में ट्रम्प ने कोई विवादित बयान भी नहीं दिया। मनीला में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रम्प ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन से मुलाकात की संभावना जताई। इस बैठक के लिए शेन्झेन को चुनने के पीछे रूस की सोच के बारे में बताते हुए, वाशिंगटन स्थित स्टिमसन सेंटर की सुन युन ने कहा, ह्यरूस संभवतः इस शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल चीन और अमेरिका को यूक्रेन के मुद्दे पर मॉस्को के रुख के करीब लाने के लिए करेगा।ह्न सुन ने आगे कहा कि चीन हथियारों के नियंत्रण, यूक्रेन या ईरान जैसे मुद्दों पर बातचीत में शामिल नहीं होगा; वह बस यही कहता रहेगा कि शांति जरूरी है और युद्ध खत्म होने चाहिए।

तीनों नेता मिलकर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने, ईरान से शांति की पहल करने के वास्ते आगे बढ़ते हैं, तो शायद बहुध्रुवीय विश्व की अर्थव्यवस्था पटरी पर आये। ट्रम्प के पास अब नेतन्याहू जैसा उग्र और अहंकारी साथी नहीं है, इसलिए वह इस बार अपने बयानों के जरिये ह्यटैरिफ बमह्न नहीं बरसा रहे हैं। फरवरी 2026 में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि समाप्त होने के बाद ट्रंप हथियारों पर नियंत्रण के लिए नई और आधुनिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। शेन्झेन में इसपर भी बात होगी।

लेखक जियो-पॉलिटिकल मामलों के पत्रकार हैं।

अनियंत्रित उपभोक्तावाद से उपजा पर्यावरण संकट

चिंतन-मनन

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी ह्यस्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर कॉप-31ह्न नामक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि जनवरी से सितंबर, 2026 के बीच पृथ्वी का औसत सतही तापमान 19वीं सदी के उत्तरार्ध (1850ङ्क1900) में दर्ज औसत तापमान की तुलना में लगभग 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस रिपोर्ट में तापमान की वृद्धि को समझने के लिए 1850 से 1900 के बीच की अवधि को आधार माना गया है, जिसे जलवायु विज्ञान में पूर्व-औद्योगिक संदर्भ अवधि कहा जाता है। वहीं, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर द्वारा जारी ह्यविदाउट रैपिड एक्शन, द वर्ल्ड इज हेडिंग टू इर्रिकवरेबल ओवरशूटह्न नामक रिपोर्ट में भी वैश्विक जलवायु प्रयासों की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन को रोकने के सामूहिक वैश्विक प्रयास लगातार पांचवें वर्ष लगभग ठहर गए हैं। वर्तमान सरकारी नीतियों के आधार पर इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है।

जलवायु परिवर्तन का संकट अब भविष्य की कोई आशंका भर नहीं रह गया है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में घट रही घटनाएं इस संकट की बढ़ती गंभीरता का संकेत दे रही हैं। जुलाई, 2019 में पश्चिमी यूरोप के कई देशों को अविश्वसनीय रूप से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। बेल्जियम और नीदरलैंड में तापमान पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फ्रांस में जुलाई की भीषण गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया और कई लोगों की मौत का कारण बनी। वहीं, अप्रैल और मई, 2024 में दक्षिणी ब्राजील के रियो ग्रांडे दो सुल राज्य में हुई मूसलाधार बारिश ने विनाशकारी बाढ़ का रूप ले लिया और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े।

इन घटनाओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय समूह ह्यवर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशनह्न के निष्कर्ष बताते हैं कि मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ रहा जलवायु परिवर्तन ऐसी भीषण गर्मी और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की संभावना तथा तीव्रता को बढ़ा रहा है। मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। इस तथ्य को जलवायु वैज्ञानिक अपने विभिन्न अध्ययनों में लगातार रेखांकित कर रहे हैं।

आपके पत्र

अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों ?

देश में आम चुनाव का मौसम है। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ राजनेता अभद्र, बेतुकी बयानबाजी भी इस दौरान करते हैं। हाल ही में कंगना रनौत और ममता बनर्जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, वो मामला सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश में सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस से संबंधित हैं, द्वारा कंगना रनौत पर जो भद्दी टिप्पणी का मामला सामने आया है, उसके लिए सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्ट किया है कि यह टिप्पणी उनके द्वारा नहीं कि गई है। उन्होंने कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को बहुत से लोग प्रयोग करते हैं। यह टिप्पणी किसी और ने की है, लेकिन सुप्रिया को अपने सोशल साइट्स के अकाउंट को सबके साथ साझा करने की क्या जरूरत थी? दूसरी तरफ ममता पर टिप्पणी भी निंदनीय है।

मनीषा चौधरी,रांची

मेट्रो रेज की ओर से स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक जीतेन्द्र कुमार सिंह के लिए जेके न्यूज नेटवर्क, पिपरटोली, अरगोड़ा, रांची 834002 (झारखंड) से प्रकाशित तथा शिवासाईं पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नियर टेंडर बागीचा, पेट्रोल पंप रातू रोड, रांची , (झारखंड) से मुद्रित।

प्रधान संपादक : जीतेन्द्र कुमार सिंह, **संपादक** : लाल दिवाकर नाथ शाहदेव*, *पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार। समस्त दिवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवाइयों एवं दंडित परिवादों के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। फोन : 7369017908, R.N.I. No.-JHAHIN/2017/75028 **website :** www.metrorays.in

email : metrorays.ranchi@gmail.com

न्यूज IN ब्रीफ

सकरीगली उच्च विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी पढ़ाई हो रही प्रभावित

साहिबगंज : जिले के नवसृजित उच्च विद्यालय सकरीगली में शिक्षकों की भारी कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।विद्यालय में शिक्षकों की कमी को देखते हुए लता बिहारी मंडल को प्रतिनियोजन के आधार पर सकरीगली उच्च विद्यालय में पदस्थापित किया गया था।लेकिन 10 अक्टूबर 2026 को उन्हें पुनः बरहेट भेज दिए जाने के बाद विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।इस संबंध में आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक रणधीर प्रसाद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी साहिबगंज को आवेदन देकर विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षक के वापस चले जाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है।विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं रहने से शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना भी मुश्किल हो रहा है।उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग की है कि लता बिहारी मंडल को पुनः सकरीगली उच्च विद्यालय में प्रतिनियोजित किया जाए।साथ ही विद्यालय में शिक्षकों की कमी को देखते हुए अन्य शिक्षकों का भी प्रतिनियोजन किया जाए,ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके।

राजमहल के टिक्काटोला में किशोरी को लगी गोली

साहिबगंज : राजमहल थाना क्षेत्र के टिक्काटोला गांव में गुरुवार शाम गोलीकांड की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।इस घटना में 15 वर्षीय गौरी कुमारी,पिता केदारनाथ मंडल,गोली लगने से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि शाम करीब 7:15 बजे किशोरी के दाहिने पैर में गोली लगी।घटना के बाद परिजनों एवं स्थानीय लोगों की मदद से घायल किशोरी को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल पहुंचाया गया,जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है।घटना की सूचना मिलते ही राजमहल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी।पुलिस को घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद हुआ है।जिसे जांच के लिए अपने कब्जे में लिया गया है।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार,पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है।हालांकि,गोली चलने के वास्तविक कारण और घटना में शामिल लोगों की भूमिका को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है।घटना के बाद से टिक्काटोला गांव में चचाओं का बाजार गर्म है।पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

अवैध बालू परिवहन कारोबारियों ने सीओ पर किया जानलेवा हमला, प्राथमिकी दर्ज

बरकट्ठा : बरकट्ठा में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करना बीडीओ सह सीओ सुमन कुमार सौरभ को भारी पड़ गया। बालू कारोबारियों ने न केवल उनके सरकारी काम में बाधा डाली, बल्कि उन पर जानलेवा हमला करने का भी प्रयास किया। इस गंभीर घटना को लेकर सीओ सुमन कुमार सौरभ ने गोरहर थाना में आवेदन देकर कांड संख्या 42/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार 19 नवंबर की रात करीब 7 बजे सीओ सुमन कुमार सौरभ हजारीबाग से बरकट्ठा लौट रहे थे। इसी दौरान बंडासिंघा मोड़ के पास बिना नंबर के अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को रोककर उन्होंने चालक से चालान और वैध कागजात मांगे। इसी बीच बंडासिंघा मोड़ स्थित दुर्गा मिष्ठान दुकान के पास बैठे कुछ लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। आरोप है कि हमलावरों ने पहले ट्रैक्टर चालक को मौके से भगाया और फिर दूसरे व्यक्ति के जरिए बालू लदा ट्रैक्टर भी वहां से निकलवा दिया। सीओ ने बताया कि हमलावर उनकी सरकारी गाड़ी में जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे और गाड़ी का शीशा खुलवाने की कोशिश करते हुए धमकी दे रहे थे कि आज के बाद बालू की गाड़ी पकड़ने पर वे बचेंगे नहीं। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सीओ ने तुरंत गाड़ी के दरवाजे बंद किए और गोरहर थाना पुलिस को सूचना दी। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गये। घटना के दौरान सीओ ने पूरे वाकये का वीडियो बना लिया था, जिसे हमलावरों ने छीनने की भी कोशिश की। ताकि वीडियो फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा सकी। इनमें बंडासिंघा निवासी किशोर मोदी (पिता स्व बाडी मोदी), किशोर साव (पिता बहादुर साव), महेंद्र साव (पिता अर्जुन साव), मां दुर्गा मिष्ठान के संचालक, दुकान के कर्मी और 6-7 अन्य अज्ञात लोग शामिल हैं। दर्ज एफआईआर में सरकारी कार्य में बाधा डालने, जान से मारने का प्रयास, आर्म्स एक्ट, मॉब लिंचिंग और अवैध बालू सिंडिकेट चलाने वाले माफिया रैकेट से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गये हैं।

वहीं दूसरी ओर दुर्गा मिष्ठान भंडार के संचालक किशोर साव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान बीडीओ सह सीओ के चालक ने मिठाई की मांग की। मिठाई नहीं देने पर उन्होंने चालक के माध्यम से दुकान संचालक को बुलवाया। तत्पश्चात बीडीओ सह सीओ ने उनसे फूड लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की। इस पर चुप रहने के बाद उन्होंने कथित तौर पर बर्बाद कर देने की धमकी दी।वहीं घटना के बाद क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार को लेकर चचाओं का बाजार गर्म है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीसी व एसपी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण

रामगढ़ : मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन के आगामी 27 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम के सफल, सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त रामगढ़ ऋतुराज एवं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने संयुक्त रूप से गोला प्रखंड अंतर्गत बरलंगा पंचायत के लुकैयाटांड स्थित प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल की भौतिक स्थिति, उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था संधारण से संबंधित विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान संभावित भीड़, आगंतुकों एवं आम नागरिकों के आवागमन, वाहनों के परिचालन, पार्किंग व्यवस्था तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ऋतुराज ने संबंधित पदाधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं ससमय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल की साफ-सफाई, समुचित बैरिकेडिंग, पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, निर्बाध आवागमन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं को लेकर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही, कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया। वहीं, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी, यातायात प्रबंधन एवं भीड़ नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

साहिबगंज के शिक्षक मनोहर शर्मा को मिला नालंदा शिक्षा गौरव सम्मान

पटना में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने किया सम्मानित जिले का बढ़ाया मान

संवाददाता



साहिबगंज : शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पण को देखते हुए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट कन्या विद्यालय साहिबगंज के शिक्षक मनोहर शर्मा को प्रतिष्ठितह्यनालंदा शिक्षा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। पटना स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की गरिमामयी उपस्थिति में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।उनकी इस उपलब्धि से साहिबगंज जिले के शिक्षा जगत में खुशी की लहर है।यह सम्मान समारोह वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल एवं शिक्षा प्रदर्शनी के साथ आयोजित किया गया था। इसमें पूर्वी भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षण कंपनियों और तकनीकी संगठनों ने भाग लिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य आधुनिक शिक्षा प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक,नवीन शिक्षण पद्धतियों कौशल विकास तथा भविष्य की शिक्षा की संभावनाओं पर चर्चा करना था।सम्मान प्राप्त करने के बाद शिक्षक मनोहर शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव ला रही है।ऐसे आयोजन शिक्षकों को आधुनिक तकनीक और नवीन शिक्षण कौशल से जोड़ने के साथ विद्यार्थियों को भी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से पढ़ाई को अधिक सरल,रोचक,प्रभावी और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सकता है।मनोहर शर्मा लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधि आधारित शिक्षण, रचनात्मक नवाचार,कम लागत वाली शिक्षण-अधिगम सामग्री के निर्माण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।उनका मानना है कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों में रचनात्मकता व्यावहारिक ज्ञान और नई चीजें सीखने की क्षमता का भी विकास होना चाहिए।उनकी इस उपलब्धि को साहिबगंज जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।ह्यनालंदा शिक्षा गौरव सम्मानह्न से सम्मानित होना न केवल मनोहर शर्मा की व्यक्तिगत मेहनत,लगन और शैक्षणिक प्रतिबद्धता का परिणाम है,बल्कि इससे साहिबगंज सहित पूरे झारखंड का मान भी बढ़ा है।जिले के शिक्षाविदों और शिक्षा प्रेमियों ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है।

अंतरराष्ट्रीय कुश्ती दंगल में पहुंचे यादव महासभा के रामाशीष यादव

अध्यक्ष रामाशीष यादव से दिनेश कुमार यादव ने की मुलाकात संगठन विस्तार पर हुई चर्चा

संवाददाता



साहिबगंज : अंतरराष्ट्रीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में झारखंड प्रदेश यादव महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष यादव के साहिबगंज पहुंचने पर झारखंड प्रदेश यादव महासभा के पूर्व साहिबगंज जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने एक होटल में उनसे मुलाकात की।दिनेश कुमार यादव ने उन्हें बुके एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया।मुलाकात के दौरान दोनों के बीच संगठन के विस्तार,मजबूती और समाज को एकजुट करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।दिनेश कुमार यादव ने यादव महासभा को जिला एवं प्रखंड स्तर पर मजबूत बनाने तथा समाज के अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने पर जोर दिया।इस अवसर पर संगठन की भावी गतिविधियों और सामाजिक एकजुटता को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया।मौके पर विक्की यादव,राजेश यादव विमल,यादव,रंजीत यादव छोटू यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे।

रानीचुवां पंचायत में किसानों को टिकाऊ खेती का प्रशिक्षण

बरही : रानीचुवां पंचायत भवन में में मानव विकास की ओर से किसानों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को टिकाऊ और लाभकारी खेती के तरीके बताए गए। प्रशिक्षण में प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) राकेश कुमार और अन्य विशेषज्ञों ने मृदा स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, जैविक खेती और जलवायु अनुकूल फसल योजना की जानकारी दी। किसानों को मिट्टी की जांच, संतुलित उर्वरक के उपयोग, जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के तरीके बताए गए। फसल चक्र अपनाने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की सलाह दी गई।

बजरंगी प्रसाद यादव ने किया शक्तिमान स्वीट्स मिठाई कारखाने का उद्घाटन



संवाददाता

साहिबगंज/राजमहल : मुरली हाल्ट में शुक्रवार को शक्तिमान स्वीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भव्य उद्घाटन हुआ।भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने फीता काटकर प्लांट का उद्घाटन किया।इस अवसर पर शक्तिमान स्वीट्स के प्रोपराइटर मिठुन यादव ने मुख्य अतिथि बजरंगी प्रसाद यादव को बुके एवं अंगवस्त्र भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत एवं सम्मानित किया।इस दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति,व्यापारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।बताया गया कि शक्तिमान स्वीट की तीनपहाड़,उधवा और इंग्लिश में पहले से तीन शाखाएं संचालित हो रही हैं।अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू होने से जिले के लोगों को शुद्ध, स्वच्छ और सस्ती मिठाई आसानी से उपलब्ध होगी।

प्लांट के ऑनर मिथुन कुमार यादव ने बताया कि जिले में हजारों मिठाई की दुकानें हैं,लेकिन शुद्धता के मामले में शक्तिमान स्वीट का कोई मुकाबला नहीं है।उन्होंने कहा कि दुकानों में तरह-तरह की मिठाई तो मिल जाती है,लेकिन ग्राहक कभी कारखाना जाकर नहीं देखते कि मिठाई किस स्थिति में बनाई जा रही है।उन्होंने बताया कि इस प्लांट में मिठाई बनाने के लिए गैस,कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।इसकी जगह बॉयलर प्लांट से स्टीम के माध्यम से मिठाई,पनीर और खोया बनाया जाएगा।इससे मिठाई में धुआं,राख और मिलावट की संभावना नहीं रहेगी और मिठाई पूरी तरह शुद्ध बनेगी।मिथुन कुमार यादव ने बताया कि आने वाले दिनों में राजमहल और साहिबगंज में भी शक्तिमान स्वीट की शाखा खोली जाएगी।वर्तमान में जहां बस की सुविधा है,वहां दुमका,देवघर, रांची जैसे स्थानों पर ड्राई स्वीट भेजी जा रही है।शादी-विवाह आदि में आर्डर देने पर ग्राहकों को मिठाई बनवाने की लागत से भी कम कीमत में यहां से मिछाई उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अवसर पर बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि जिले में स्टीम के द्वारा मिठाई का मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत बड़ी उपलब्धि है।इतनी शुद्धता से मिठाई बनाना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जिले में हर व्यक्ति को घर तक सस्ती और शुद्ध मिठाई मिलेगी,जिसकी कमी आज तक थी, उसे इस प्लांट ने पूरा कर दिया।उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में शक्तिमान स्वीट का नाम हर व्यक्ति की जुबान पर होगा।मौके पर राजकिशोर यादव, मनोज यादव, पंकज घोष,राजेश यादव, राहुल यादव, श्यामबिहारी यादव, जगमोहन सिंह, कुंदन सिंह, अभय सिंह, दिलीप यादव, आशीष यादव, बबलू घोष, शोभा यादव, महेन्द्र यादव, राजेन्द्र यादव, रामखेलावन यादव सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।

पंकज मिश्रा ने किया रेड एंड टेलर शोरूम का भव्य उद्घाटन



साहिबगंजःशहर के कॉलेज रोड स्थित पूर्वी फाटक के समीप शुक्रवार को रेड एंड टेलर रेडीमेड शोरूम का भव्य उद्घाटन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने फीता काटकर किया।उनके गरिमामयी उपस्थिति में शुरू हुए इस शोरूम से शहरवासियों को फैशन और ब्रांडेड परिधानों की खरीदारी के लिए एक नया विकल्प मिला है।शोरूम में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन के सूटिंग-शर्टिंग,पैंट,कोट, ब्लेजर सहित विभिन्न प्रकार के आधुनिक परिधान उपलब्ध कराए गए हैं।खासकर शादी-विवाह,पारिवारिक समारोह और अन्य विशेष अवसरों के लिए ग्राहकों को अपनी पसंद और बजट के अनुरूप कपड़ों की खरीदारी करने का अवसर मिलेगा।इस अवसर पर शोरूम के प्रोपराइटर सोमनाथ शर्मा ने बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य केवल कपड़ों की बिक्री करना नहीं,बल्कि ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता,आकर्षक डिजाइन और उचित कीमत पर बेहतरीन परिधान उपलब्ध कराना है।उन्होंने कहा कि अब साहिबगंज के लोगों को ब्रांडेड कपड़ों की खरीदारी के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।वे अपने ही शहर में बजट के अनुसार मनपसंद कपड़ों की खरीदारी कर सकेंगे।रेड एंड टेलर शोरूम के शुभारंभ को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा गया।उद्घाटन के दौरान खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी।शोरूम के खुलने से साहिबगंज के स्थानीय बाजार में फैशन और रेडीमेड कपड़ों के कारोबार को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। मौके पर भाजपा नेता गणेश तिवारी, डॉ.सुमित कुमार, बोदी सिन्हा, सज्जन पोद्दार, शाहिद खान,सुनील भारतीय, अंकित केजरीवाल, डॉ.सुरेंद्र नाथ तिवारी,सोनू अग्रवाल, वार्ड पार्षद वर्षा कुमारी, दीपा देवी, विनीत शर्मा, अनुज कुमार, प्रशांत शेखर, पंकज कुमार सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

बीरभूम से साहिबगंज पहुंचे पर्यटकों ने किया प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार

प्राकृतिक सुंदरता पहाड़ पर्वत शिवगादी और मोती झरना की खूबसूरती को मोबाइल कैमरे में कैद कर साथ ले गए पर्यटक



साहिबगंज : झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शिरडी से पहुंचे पर्यटकों का दो दिवसीय साहिबगंज भ्रमण शुक्रवार को संपन्न हो गया।दो दिनों तक पर्यटकों ने साहिबगंज की प्राकृतिक वादियों, ऊंचे पहाड़ों,चट्टानों,प्रसिद्ध शिवगादी धाम और मोती झरना सहित विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया।वहीं अंतिम दिन मां गंगा के दर्शन और गंगा स्नान के बाद सभी पर्यटक अपने गृह जिले बीरभूम के शिरडी के लिए रवाना हो गए।इस दौरान पर्यटकों ने साहिबगंज की प्राकृतिक खूबसूरती, गंगा की अविरल धारा,पहाड़ों और विशाल चट्टानों के मनमोहक दृश्यों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। पर्यटकों ने यहां बिताए दो दिनों को यादगार बताते हुए साहिबगंज की प्राकृतिक छटा और यहां के धार्मिक व पर्यटन स्थलों की सराहना की।इस अवसर पर सुमित कुमार ने साहिबगंज की विशेषताओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि साहिबगंज झारखंड का एक ऐसा खूबसूरत जिला है,जहां प्रकृति, पहाड़, जंगल और मां गंगा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।यहां की प्राकृतिक चट्टानें,पहाड़ी क्षेत्र, शिवगादी धाम और मोती झरना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।उन्होंने कहा कि साहिबगंज में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यदि यहां के पर्यटन स्थलों का बेहतर प्रचार-प्रसार और सुविधाओं का विकास किया जाए तो पश्चिम बंगाल सहित दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच सकते हैं।उन्होंने साहिबगंज के लोगों के आतिथ्य और अपनापन की भी प्रशंसा की।गौरतलब है कि साहिबगंज और पश्चिम बंगाल के बीच वर्षों पुराना सामाजिक एवं सांस्कृतिक रिश्ता रहा है।रेलवे के पुराने दौर में साहिबगंज की नॉर्थ कॉलोनी,झरना कॉलोनी और बंगाली टोला सहित कई इलाकों में बंगाली समुदाय की अच्छी-खासी आबादी निवास करती थी।समय के साथ रोजगार और अन्य कारणों से कई परिवार यहां से दूसरे स्थानों पर चले गए,लेकिन आज भी इस क्षेत्र में बंगाली भाषा और संस्कृति से जुड़ी परंपराओं की झलक देखने को मिलती है।इसी पुराने रिश्ते और सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण पश्चिम बंगाल के बीरभूम सहित विभिन्न जिलों से लोग समय-समय पर साहिबगंज घूमने आते रहते हैं। पर्यटकों का कहना है कि साहिबगंज की प्राकृतिक सुंदरता और मां गंगा के दर्शन उन्हें बार-बार यहां आने के लिए प्रेरित करते हैं। दो दिनों के इस भ्रमण के बाद पर्यटक अपने साथ साहिबगंज की खूबसूरत यादें और यहां के प्राकृतिक नजारों की तस्वीरें लेकर वापस लौट गए।मौके पर झूमा घोष,बापी घोष,सोम रावत,सुजीत कुमार,अनूप कुमार रावत सहित अन्य लोग मौजूद थे।

मातृभूमि के गाने मदिरापान में सलमान खान के शानदार डांस मूव्स देख नेटिजेंस हुए दीवाने

मदिरापान को हिमेश रेशमिया द्वारा कंपोज और मुदस्सर खान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है। यह फुट टैपिंग गाना म्यूजिक, मस्ती और भाईचारे का जश्न मनाता है। एनर्जी को बढ़ाते हुए, मातृभूमिः मे वॉर रेस्ट इन पीस के लेटेस्ट ट्रैक मदिरापान में सलमान खान ने अपने सिग्नेचर डांस स्टाइल और एफर्टलेस स्वैग के साथ अपनी वापसी की है।



यह गाना खुद में आर्मी लाइफ की मस्ती और भाईचारे को लिए हुए है। इस गाने में सलमान खान अपनी स्क्वॉड के साथ मस्ती से भरा डांस और जश्न के जरिए बॉन्डिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की केमिस्ट्री इसके विजुअल अपील को और बढ़ाती है। इस तरह से गाने की खुद की तरफ खींचने वाली एनर्जी, चार्म और हर फ्रेम में जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस, सभी के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं हैं। हिमेश रेशमिया के कैची कंपोजिशन, मुदस्सर खान की जबरदस्त कोरियोग्राफी और समीर अंजान द्वारा लिखे गए बोल के साथ मदिरापान ऐसा गाना है, जो हर पार्टी में अपनी जगह बनाते हुए, चार्टबस्टर बनाने वाला है। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। फिल्म के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की कमान जियो स्टूडियोज ने संभाली है, जबकि ओवरसीज इसका डिस्ट्रीब्यूशन जी स्टूडियोज द्वारा किया जा रहा है। मातृभूमिः मे वॉर रेस्ट इन पीस में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह भी अहम रोल में स्क्रीन शेयर करती नजर आने वाली हैं।

सैफ अली खान को मिली धमकी, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के वांटेड आरोपी जीशान अख्तर का नाम आया सामने

बॉलीवुड कलाकारों को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अभिनेता सैफ अली खान को धमकी मिलने की खबर सामने आई है।

सूत्रों के मुताबिक, इस बार धमकी देने के पीछे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड आरोपी जीशान अख्तर का नाम सामने आया है। मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि धमकी वास्तव में जीशान अख्तर ने ही दी है या किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके नाम का इस्तेमाल किया है।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस धमकी की प्रामाणिकता और उससे जुड़े डिजिटल सबूतों की पड़ताल कर रही है। फिलहाल सैफ अली खान की ओर से इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है।

इससे पहले भी बॉलीवुड के



कई कलाकारों को धमकी भरे मैसेज और ऑडियो क्लिप मिल चुके हैं। हाल ही में अभिनेता तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को धमकी मिलने के मामले ने भी काफी चर्चा बटोरी थी।

इन मामलों की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से 30 वर्षीय वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा होने का दावा करते हुए कलाकारों को डराने और उनसे पैसे वसूलने की कोशिश की थी। हालांकि, शुरूआती जांच में उसके किसी गैंग से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैभव मिश्रा आईटी इंजीनियर है। पुलिस को शक था कि उसने धमकी देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से आवाज तैयार की थी। उसने ऑनलाइन सर्च के जरिए कलाकारों के संपर्क नंबर जुटाए और फिर उन्हें धमकी भरे मैसेज भेजे। तुषार कपूर को भेजे गए एक ऑडियो मैसेज में कथित तौर पर पांच करोड़ रुपए की मांग की गई थी। मैसेज भेजने वाले ने खुद को गैंगस्टर हैरी बॉक्सर बताया था, लेकिन पुलिस की ओर से वॉयस सैंपल की जांच में यह आवाज हैरी बॉक्सर से मेल नहीं खाई थी।

अभिनेत्री सामंथा के घर गूंजी किलकारी, एक्ट्रेस ने दिया बेटे को जन्म, तस्वीर शेयर कर बताया नन्हे मेहमान का नाम



अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु के जीवन में खुशियों ने दस्तक दी है और उनके घर नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजी है। सामंथा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद प्यारी और भावुक तस्वीर साझा करते हुए अपने लाखों फैंस को यह बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर खुशी की लहर दौड़ गई है और बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तक के तमाम सेलेब्स और प्रशंसक इस जोड़ी को ढेरों बधाइयां दे रहे हैं।

तस्वीर में दिखी नन्हे हाथों की झलक, एक्ट्रेस ने किया बेटे के नाम का खुलासाः सामंथा द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस दिल छू लेने वाली तस्वीर में उनके नवजात बेटे का नन्हा हाथ नजर आ रहा है। फोटो में बच्चा बड़े प्यार से अपने पिता का हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रहा है, जबकि मां सामंथा उस नन्हे बच्चे का हाथ थामे हुए हैं। इस खूबसूरत पल को फैंस के साथ साझा करते हुए सामंथा ने कैप्शन में अपने बेटे के नाम और जन्म की तारीख का भी खुलासा किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि हमारा प्यारा बेबी बॉय, देव निदिमोरु, 19.11.2026, हमारा दिल इससे ज्यादा खुश कभी नहीं रहा।

सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता, सेलेब्स ने लुटाया प्यार

: सामंथा की इस पोस्ट के शेयर होते ही कमेंट सेक्शन में शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई है। 19 नवंबर 2026 को दुनिया में आए नन्हे देव निदिमोरु के स्वागत में मनोरंजन जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने अपनी खुशी जाहिर की है। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के कई सितारों ने पोस्ट पर कमेंट कर सामंथा और राज को जीवन के इस नए अध्याय के लिए शुभकामनाएं दी हैं। फैंस भी इस खास पोस्ट पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।

हनुमान अंश के लिए विशाल चतुर्वेदी को मिला इंडियन ऑफ दि ईयर 2026 अवार्ड



फिल्म हनुमान अंश के लेखक, निर्देशक और निमार्ता विशाल चतुर्वेदी को फिल्म के निर्माण में उनकी रचनात्मक सोच, मेहनत और योगदान के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2026 सम्मान से नवाजा गया है। विशाल चतुर्वेदी ने इस उपलब्धि को अपनी पूरी टीम और फिल्म से जुड़े सहयोगियों को समर्पित करते हुए कहा कि उनके विश्वास और अथक प्रयासों के बिना इस फिल्म को साकार करना संभव नहीं था। सम्मान समारोह में मंच पर पहुंचते ही विशाल चतुर्वेदी ने सीता राम कहकर अपने संबोधन की शुरूआत की।

उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि हमारे देश में माताओं और बहनों को पहले स्थान दिया जाता है, इसलिए उनके विचार से यह संबोधन अधिक उपयुक्त है। उन्होंने हनुमान अंश के निर्माण के अनुभव साझा करते हुए कहा कि फिल्म को बनाने का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। हालांकि, निर्माताओं के विश्वास और पूरी टीम की मेहनत ने इस मुश्किल यात्रा को संभव बनाया। विशाल ने अपने संबोधन में सबसे पहले फिल्म की निमार्ताओं रागिनी सोना और नम्रता सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रागिनी सोना ने उनकी रचनात्मक सोच पर भरोसा किया और फिल्म के निर्माण के दौरान उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी। एक फिल्मकार के लिए निमार्ता का विश्वास बेहद महत्वपूर्ण होता है।

उन्होंने कहा कि जब निर्माता या टीम के सदस्य फिल्मकार के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं, तो उसकी रचनात्मकता प्रभावित होती है, लेकिन उन्हें इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। इस अवसर पर विशाल ने फिल्म के 25 वर्षीय कार्यकारी निमार्ता पीयूष सिंह ठाकुर को भी मंच पर आमंत्रित किया और फिल्म के पहले दिन से उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीयूष के समर्पण और मेहनत के बिना हनुमान अंश का निर्माण संभव नहीं हो पाता। उन्होंने फिल्म के भक्ति गीत मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को अपनी आवाज देने वाले गायक एवं संगीतकार सुनील लोधी का भी विशेष रूप से आभार जताया। यह गीत फिल्म के शुरूआती लोकप्रिय गीतों में शामिल है और दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुका है। विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म में नीम करौली बाबा महाराज की भूमिका निभाने वाले शोभिनव सत्य को भी मंच पर आमंत्रित किया। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम और उन सभी सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिन्होंने अपने परिश्रम, समर्पण और विश्वास से इस परियोजना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्मान प्राप्त करने के अवसर को विशाल चतुर्वेदी ने केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि हनुमान अंश से जुड़े सभी सहयोगियों की सामूहिक सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। इंडियन ऑफ द ईयर 2026 का सम्मान उनके फिल्मी सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

प्रियंका चोपड़ा की बेटी ने अपनी प्यारी आवाज में गाया गायत्री मंत्र, एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो



ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने व्यस्त शूटिंग शेड्यूल के बीच भी मदरहुड के हर पल को खूबसूरती से जी रही हैं। काम की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वह अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास के साथ वक्त बिताने का कोई मौका नहीं चूकतीं और अक्सर उन्हें अपने साथ फिल्म के सेट पर भी ले जाती हैं। हाल ही में प्रियंका ने सोशल मीडिया पर मालती के साथ बिताए कुछ बेहद खास और प्यारे पलों की झलक साझा की है, जिसमें नन्ही मालती का गायत्री मंत्र गाते हुए वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है।

घर के मंदिर के सामने मालती ने गाया गायत्री मंत्र, सेट पर बनीं प्रोड्यूसरः प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपनी छुट्टियों और काम से जुड़ी कई तस्वीरें व वीडियो शेयर किए हैं। कुछ तस्वीरों में मां-बेटी की जोड़ी समुद्र किनारे मस्ती करती नजर आई, जहां मालती रेत पर कुछ बना रही थीं और प्रियंका धूप का आनंद ले रही थीं। एक अन्य तस्वीर में पूरा परिवार समुद्र की लहरों पर सर्फिंग करता दिखाई दिया। वहीं, फिल्म के सेट से सामने आई तस्वीरों में मालती ने प्रोड्यूसर लिखे हुए हेडफोन पहन रखे थे और वह स्क्रिप्ट पढ़ती हुई नजर आईं। हालांकि, जिस वीडियो ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, उसमें प्रियंका अपने घर के एक छोटे से मंदिर के सामने बैठी हैं और उनकी गोद में बैठी मालती बेहद प्यारी आवाज में गायत्री मंत्र गा रही हैं। इस दौरान प्रियंका ने भी मालती की सुरीली आवाज की जमकर सराहना की। इन तस्वीरों को साझा करते हुए प्रियंका ने कैप्शन में लिखा कि वह हाल ही में काम में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर हैं।

सोशल मीडिया पर फैंस ने लुटाया प्यार, बताया भविष्य की पॉपस्टारः मालती का यह प्यारा वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर छाया हुआ है और फैंस लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने मालती की तारीफ करते हुए लिखा कि क्या आवाज है, तो दूसरे ने उन्हें भविष्य की कलाकार, प्रोड्यूसर और गायिका बताया। एक अन्य फैन ने कमेंट किया कि मालती की आवाज बिल्कुल किसी पॉपस्टार जैसी है और बेहद सुंदर है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब प्रियंका अपनी बेटी को काम पर साथ लेकर गई हों। इससे पहले भी वह फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट की शूटिंग के दौरान मालती को अपने साथ ले गई थीं और वाराणसी की शूटिंग के वक्त भी उन्हें भारत लेकर आई थीं।

8 साल बाद राजामौली की 1000 करोड़ की फिल्म वाराणसी से करेंगी वापसीः वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा आठ साल के लंबे अंतराल के बाद फिल्म वाराणसी के जरिए भारतीय सिनेमा में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिग्गज निर्देशक एस.एस. राजामौली के निर्देशन में बन रही इस भव्य फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। अलग-अलग समय-कालों और स्थानों से गुजरने वाले एक रोमांचक सफर पर आधारित इस फिल्म में भारतीय इतिहास से प्रेरित कई अहम पहलू शामिल हैं। करीब 1,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में तैयार हो रही यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, जिसे अप्रैल 2027 में रिलीज किया जाएगा।

सैंडपेपर विवाद में पैट कमिंस के समर्थन में उतरे हेजलवुड, कप्तानी से हटे तो छोड़ सकते हैं टीम!



सिडनी : ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में 2018 के चर्चित सैंडपेपर विवाद ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। बॉल टैंपरिंग को लेकर नए आरोप सामने आने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में अलग-अलग राय देखने को मिल रही हैं। इस बीच तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड खुलकर टेस्ट कप्तान पैट कमिंस के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर इस विवाद के चलते कमिंस को कप्तानी से हटाया जाता है, तो वह भी टीम छोड़ने पर विचार कर सकते हैं।

दरअसल, उस्मान ख्वाजा, डेविड वॉर्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने हाल ही में दावा किया है कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान टीम के कई खिलाड़ियों को सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी थी। हालांकि, पैट कमिंस पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वह इस योजना का हिस्सा नहीं थे। अब 35 वर्षीय तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने भी कमिंस का बचाव किया है।

हेजलवुड ने कोड स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि अब ऑस्ट्रेलियाई टीम कभी सैंडपेपर का इस्तेमाल नहीं करेगी और इस स्थिति से टीम को बाहर निकालने में पैट कमिंस की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि कमिंस ने शानदार काम किया है और वह बेहतरीन कप्तान हैं। टीम के किसी भी खिलाड़ी से पूछने पर यही जवाब मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पहले टेस्ट में कमिंस कप्तान नहीं रहे, तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि टीम आगे कैसे बढ़ेगी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 9 दिसंबर से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। इससे पहले कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने दावा किया था कि पैट कमिंस को बॉल टैंपरिंग की जानकारी थी। ऐसे में अगर इन आरोपों के आधार पर कमिंस को कप्तानी से हटाया जाता है, तो टीम के भीतर असहज स्थिति पैदा हो सकती है।

हेजलवुड ने आगे कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो उन्हें भी एक कठिन फैसला लेना पड़ सकता है। उन्होंने साफ किया कि सैंडपेपर विवाद के समय उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी और वह इस मामले में शामिल नहीं थे। उधर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरे विवाद की जांच कराने की बात कही है। बोर्ड का कहना है कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए जांच की जाएगी। ऐसे में अब सभी की नजरें जांच के नतीजों और कमिंस की कप्तानी को लेकर होने वाले फैसले पर टिकी हैं।

बारिश से मैच रद्द होने के बावजूद पाकिस्तान को बनाया चैंपियन भड़की टीम इंडिया ने किया ट्रॉफी समारोह का बहिष्कार

ढाका : भारत और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होने वाले पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारी बवाल खड़ा हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण यह खिताबी मुकाबला बिना टॉस हुए ही रद्द कर दिया गया, लेकिन इसके बाद आयोजकों के एक विवादित फैसले ने खेल भावना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के कारण मैच धुल जाने के बावजूद पाकिस्तान को टूर्नामेंट का एकमात्र विजेता घोषित कर दिया गया, जिसके विरोध में भारतीय टीम ने ट्रॉफी वितरण समारोह का बहिष्कार कर दिया। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया ने इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए



इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है और भारत तथा पाकिस्तान को संयुक्त विजेता के रूप में मान्यता देने की मांग की है।

बेहतर नेट रन-रेट का हवाला देकर पाकिस्तान को सौंपी ट्रॉफी, नियमों की अनदेखी का आरोपः मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ने के बाद मैच रेफरी ने बेहतर नेट रन-रेट का हवाला देते हुए पाकिस्तान को एशिया कप का एकमात्र चैंपियन घोषित करने का निर्णय सुनाया और ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम को सौंप दी। भारतीय टीम ने इस निर्णय को नियमों के विरुद्ध बताते हुए सम्मान समारोह में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। सीएबीआई का कहना है कि टूर्नामेंट के तकनीकी नियमों का सेक्शन 27 विशेष रूप से टाई हुए फाइनल से संबंधित है और उसमें उल्लिखित दोनों वाक्य उसी स्थिति का जिक्र करते हैं। नियमानुसार फाइनल मुकाबला टाई होने या बारिश की वजह से रद्द होने की स्थिति में दोनों फाइनलिस्ट टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाना चाहिए था।

पाक क्रिकेट अधिकारी पर तकनीकी समिति का फैसला पलटने का गंभीर आरोपः इस पूरे विवाद में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह सामने आया है कि शुरूआत में नियमों के तहत दोनों टीमों को संयुक्त विजेता बनाने पर सहमति बन गई थी। सीएबीआई के अनुसार, उन्होंने नियमों की इस व्याख्या को वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की तकनीकी समिति के समक्ष रखा था, जिस पर समिति शुरू में सहमत हो गई थी और भारत तथा पाकिस्तान को जॉइंट विनर घोषित करने पर राजी थी। हालांकि, आरोप है कि विश्व ब्लाइंड क्रिकेट परिषद और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष सुल्तान शाह ने तकनीकी समिति के इस फैसले को पलट दिया और मैच रेफरी को भी पाकिस्तान को अकेला विजेता मानने के लिए मजबूर किया।

बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंचा था भारत, 2016 में जीता था पहला खिताबः गौरतलब है कि भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने बुधवार को ढाका के बसुंधरा स्पोर्ट्स सिटी में बांग्लादेश पर आठ विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए इस टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। चूंकि लीग चरण में भारत को पाकिस्तान के हाथों महज एक विकेट से बेहद करीबी हार झेलनी पड़ी थी, इसलिए फाइनल में दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने भारत के खिताब जीतने के सपने को अधूरा छोड़ दिया। बता दें कि भारत ने साल 2016 में इस टूर्नामेंट का पहला खिताब जीता था, जबकि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया था और इस बार इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया।

आलिया भट्ट-आर्यन खान-वैभव सूर्यवंशी *टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया* की लिस्ट में

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और अभिनेता आर्यन खान से लेकर क्रिकेट के युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी तक देश की 100 उभरती प्रतिभाओं ने अमरीकी समाचार पत्रिका टाइम की प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। दुनिया की मशहूर पत्रिका टाइम ने पहली बार भारत के लिए टाइम100 नेक्स्ट इंडिया सूची जारी की है। इस सूची में फिल्म, क्रिकेट, कारोबार, विज्ञान, संगीत और सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे लोगों को शामिल किया गया है। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, टाइम100 नेक्स्ट इंडियाह्व इस सूची का पहला अंतरराष्ट्रीय संस्करण है और रिलायंस इसका प्रमुख भागीदार है। इस सूची में सिर्फ बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की हस्तियों का ही दबदबा नहीं है, बल्कि खेल जगत से हरमनप्रीत कौर, लवलीना बोरगोहेन और सानिया मिर्जा को भी इसमें जगह मिली है। संगीत के क्षेत्र से दिलजीत दोसांझ और अनिरुद्ध रविचंदर शामिल हैं।

वहीं, कारोबार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से पीयूष बंसल, अलबिंदर सिंह ढींडसा, तरुण मेहता और राधिका गुप्ता जैसे नाम शामिल हैं। विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र से अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को भी इस सूची में स्थान मिला है। टाइम100 नेक्स्ट इंडिया का भव्य आयोजन 12 दिसंबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा।

न्यूज ब्रीफ

कभी था आसमान में दबदबा, आज कर्ज के जंजाल में फंसी स्पाइसजेट,बचे सिर्फ 13 विमान



नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने लगातार फ्लाइट कैंसिल होने, देरी और ऑपरेशनल गड़बडियों को लेकर स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया है। नोटिस में एयरलाइन से सात दिनों में जवाब मांगा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2019 में देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी रही स्पाइसजेट के पास अब सिर्फ 13 विमान बचे हैं, जिनमें से 10 से भी कम उड़ान भरने की स्थिति में हैं।

कंपनी पर करीब 35 करोड़ रुपए का कर्ज है। लीज पर विमान देने वाली कंपनियों को पेमेंट नहीं कर पाने के कारण एयरलाइन से कई विमान हटाए गए हैं या ग्राउंडेड हैं। पिछले नौ महीने में कंपनी का मार्केट शेयर 3.9 फीसदी से घटकर 0.6 फीसदी हो गया है। इस साल अगस्त और सितंबर में स्पाइसजेट की हर पांच में से एक उड़ान कैंसिल हुई।

बांग्लादेश में लॉकडाउन से हाहाकार, विदेश राज्य मंत्री के घर में लगाई आग, अब तक चार की मौत



एजेंसी/ ढाका: पिछले कुछ सालों से भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वतन वापसी से पहले पड़ोसी देश में हाहाकार मचा हुआ है। प्रतिबंधित हसीना की पार्टी अवामी लीग ने देश में बंद बुलाते हुए लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से कई शहरों में जमकर हिंसा, आगजनी की घटनाएं सामने आईं।

बांग्लादेश के मंत्री हुमायूं कबीर के मकान को भी आग लगा दी गई। हालांकि, राहतभरी बात यह रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि गेट पर कोई पेट्रोल बम से हमला नहीं किया गया, बल्कि बदमाशों ने पॉलीथीन जलाकर आग लगाने की कोशिश की। मंत्री के आवास पर जहां आग लगाई गई थी, वहां सुबह गेट के लोहे पर जलने के निशान दिखाई दिए। जमीन पर राख और पॉलीथीन जली हुई पाई गई। अवामी लीग द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन और बंद के बीच बांग्लादेश में कई जगहों पर झड़पों की घटनाएं सामने आईं।अलग-अलग मामलों में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े दो नेताओं की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग की भी जान चली गई। इस तरह इन घटनाओं में कुल चार लोगों के मरने की जानकारी अब तक सामने आई है।

देश में अशांति फैलाने के लिए आगजनीः अवामी लीग द्वारा बुलाई गई हड़ताल के दौरान हुई हिंसक घटनाओं पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अवामी लीग के समर्थक देश में अशांति फैलाने के लिए आगजनी और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने जनता से एकजुट होकर आतंकवाद, हत्याओं और चुनाव में धांधली की राजनीति को फिर से शुरू करने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा।

ह्यम्मां के समान कोई छाया, आश्रय और प्रिय नहीं , सीएम योगी ने मां सावित्री देवी को नम आंखों से दी अंतिम विदाई



देहरादूनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर में अपनी मां सावित्री देवी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। उन्हें याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मां की छाया, आश्रय, सुरक्षा और प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है।

म्मुख्यमंत्री योगी अपनी मां को अंतिम विदाई देते समय भावुक नजर आए। उन्होंने पैतृक गांव पंचूर में अपनी मां के पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उन्होंने तस्वीर पर माला चढ़ाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। गहरे दुख में डूबे सीएम योगी की आंखें तब भर आईं, जब वे आखिरी बार अपनी मां के सामने खड़े थे। मां सावित्री देवी की अंतिम यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, *नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रिया॥ इसका अर्थ है- माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई आश्रय नहीं है। माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्रिय नहीं।

इसके बाद, उनकी पार्थिव देह को पंचूर से हरिद्वार ले जाया गया, जहां चंडीघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। सीएम योगी की मां के अंतिम संस्कार में भाजपा के कई नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों के पहुंचने की संभावना है। इस बीच, उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री योगी की मां सावित्री देवी को एक असाधारण महिला बताया और कहा कि उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को सही दिशा दिखाई।

म्महेंद्र भट्ट ने कहा, योगी जी ने कभी भी अपने परिवार को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों पर हावी नहीं होने दिया। वे हमेशा अपने गांव के बच्चों की चिंता करते रहे हैं। मैं उनकी माता जी को एक बहुत ही असाधारण महिला मानता हूं, जिन्होंने हमेशा अपने बच्चों को सही दिशा दिखाई। यह सौभाग्य की बात है कि किसी मां का बेटा बड़ा होकर संत बनता है।

पहले बताया था डेड इकोनॉमी, अब पढ़े कसीदे, ट्रंप ने की भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ, अमेरिकी फेड पर साधा निशाना

वॉशिंगटन डीसी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करते हुए अपने ही देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर निशाना साधा है। उन्होंने भारत की कम ब्याज दरों और 7 फीसदी की आर्थिक विकास दर का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका भी इसी तरह की नीति अपनाए तो उसकी जीडीपी ग्रोथ 14 से 15 फीसदी या यहां तक कि 20 फीसदी तक पहुंच सकती है। ट्रंप ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों को लेकर राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें टफ मैन कहा था।



व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में ब्याज दरें कम हैं और उसकी जीडीपी 7 फीसदी की दर से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं तो उसकी आर्थिक विकास दर 15 से 20 फीसदी तक पहुंच सकती है। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा होने की वजह फेडरल रिजर्व का राजनीतिक रवैया है। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए केवल फेड चेयरमैन को जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि पूरी संस्था का रवैया इसके लिए जिम्मेदार है।

ट्रंप ने आरोप लगाया कि जब भी अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अच्छे आते हैं, फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है। उनके मुताबिक, आर्थिक स्थिति मजबूत होने पर ब्याज दरें घटाई जानी चाहिए, ताकि देश की कर्ज चुकाने की क्षमता बढ़ सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसके उलट काम कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। ट्रंप का दावा है कि कम ब्याज दरों से अमेरिका तेजी से अपना कर्ज चुका सकता है और आर्थिक विकास को नई गति मिल सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके मुताबिक, अमेरिका दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सफल बनाने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि कुछ देश खुद को आर्थिक रूप से बेहद ताकतवर मानते हैं, लेकिन उनकी सफलता में अमेरिका का बड़ा योगदान है। ऐसे में अमेरिका में ब्याज दरें दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम होनी चाहिए। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब अमेरिका में महंगाई दर फेडरल रिजर्व के 2 फीसदी के निर्धारित लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (पीसीए) महंगाई दर 3.6 फीसदी रही। वहीं, खाद्य पदार्थों और ऊर्जा की कीमतों को छोड़कर मापी जाने वाली कोर पीसीए महंगाई दर 3.1 फीसदी दर्ज की गई। गौरतलब है कि फेडरल रिजर्व महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों का इस्तेमाल करता है। ट्रंप लंबे समय से केंद्रीय बैंक की इस नीति की आलोचना करते रहे हैं और ब्याज दरों में कटौती की मांग करते रहे हैं।

जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, दो से अधिक बच्चों वालों को न मिले कोई सरकारी लाभः बाबा रामदेव

गोंडा : योग गुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार को भारत में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए।

पत्रकारों से बात करते हुए रामदेव ने कहा, भारत में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाना चाहिए, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाना चाहिए। जो लोग और अधिक बच्चे पैदा करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम इसके परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में लगभग 56 देश ऐसे हैं, जिन्हें मुस्लिम-बहुसंख्यक राष्ट्र माना जाता है, जबकि करीब 60-70 देशों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है।

उन्होंने कहा, दुनिया में लगभग 56 देश ऐसे हैं, जिन्हें मुस्लिम-बहुसंख्यक राष्ट्र माना जाता है और करीब 60-70 देशों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। सभी मुसलमानों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे अत्यधिक जनसंख्या न बढ़ाएं, बल्कि ऐसे बच्चों का पालन-पोषण करें, जो बुद्धिमान, समझदार, अच्छे संस्कार वाले, नैतिक, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हों। संख्या बढ़ाने के बजाय, एक गुणवत्तापूर्ण (बेहतर) आबादी तैयार करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।



उन्होंने कहा, भारत में लगभग 99 प्रतिशत मुसलमान धर्मांतरित हैं और उनके पूर्वज एक ही हैं। सभी मुसलमानों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उनके पूर्वज भी राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, देवी-देवताओं और ऋषियों-मुनियों से जुड़े हुए थे। सभी मुसलमानों को उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। धर्म अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज, डीएनए, संस्कृति, संस्कार और नैतिक परंपराएं अलग नहीं हो सकतीं।

रामदेव ने यह भी दावा किया कि भारत में लगभग 99 प्रतिशत मुसलमान धर्मांतरित हैं।

उन्होंने कहा, भारत में लगभग 99 प्रतिशत मुसलमान धर्मांतरित हैं और उनके पूर्वज एक ही हैं। सभी मुसलमानों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उनके पूर्वज भी राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, देवी-देवताओं और ऋषियों-मुनियों से जुड़े हुए थे। सभी मुसलमानों को उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। धर्म अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज, डीएनए, संस्कृति, संस्कार और नैतिक परंपराएं अलग नहीं हो सकतीं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए रामदेव ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे महान पुत्र को जन्म दिया, जिसने वैश्विक मंच पर सनातन धर्म और राष्ट्रीय कर्तव्य की महिमा को स्थापित किया।

उन्होंने बताया कि सावित्री देवी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने उनकी दिवंगत आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना की।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए रामदेव ने उनकी आलोचना की। रामदेव ने कहा, कभी वे भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था बताते हैं, तो कभी भारत की विदेश नीति को घटिया करार देते हैं। वे भारत के मूल मूल्यों, धर्मग्रंथों और ईश्वरीय अवतारों के बारे में भी बेबुनियाद और झूठी बातें कहते हैं।

उन्होंने कहा, यह बेहद शर्मनाक है। ऐसे राजनीतिक नेता एक ऐसा काम कर रहे हैं, जिसे केवल धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पाप ही कहा जा सकता है।

भारत आए पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक को झटका, ताजमहल जाने की नहीं मिली इजाजत

नई दिल्लीः शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए पाकिस्तान के संघीय मंत्री मुसादिक मलिक का दौरा बेहद सख्त पाबंदियों और कूटनीतिक बेरुखी के बीच शुरू हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुसादिक मलिक की यह यात्रा केवल बहुपक्षीय बैठक तक ही सीमित रहेगी और उन्हें इसके अलावा कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। दरअसल, ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि पाक मंत्री आगरा स्थित ताजमहल और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाना चाहते थे, लेकिन भारतीय प्रशासन की ओर से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली है। सूत्रों का कहना है कि उन्हें भारत आने का वीजा सिर्फ एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने के लिए ही जारी किया गया है। इतना ही नहीं, जब मुसादिक मलिक नई दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर कोई भी भारतीय पदाधिकारी उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचा और केवल पाकिस्तान के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने ही उनकी अगवानी की।



सीमा पार आतंकवाद के सवाल पर साधी चुप्पी, सभ्यतागत रिश्तों पर दिया यह बयानः नई दिल्ली पहुंचने के बाद जब पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मसूद मलिक से सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत की गंभीर चिंताओं पर सवाल पूछा गया, तो वे सीधे जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा कि कल जब वे अपना आधिकारिक बयान दे देंगे, तो इस विषय पर काफी बातचीत होगी। वहीं, भारत और पाकिस्तान के सभ्यतागत रिश्तों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बातचीत हमेशा अलग-अलग पक्षों के बीच होती है, क्योंकि जब सब एक हों तो संवाद की जरूरत नहीं रहती और वहां सिर्फ एकतरफा बात होती है। उन्होंने बातचीत का अर्थ विविधता बताते हुए भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों के पुराने ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया और कहा कि खुदाई में भी इन देशों के बीच संवाद के सबूत सामने आएंगे। उन्होंने इस मंच को एक स्वागत योग्य कदम बताया।

पाक मंत्री के दौरे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का तीखा हमला, पहलगाम आतंकी हमले की दिलाई यादः दूसरी ओर, पाकिस्तानी मंत्री के भारत आने पर विपक्षी खेमे से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस दौरे पर बयान देते हुए कहा कि चूंकि एससीओ एक बहुपक्षीय मंच है और इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, इसलिए पाकिस्तान के प्रतिनिधि का बैठक में शामिल होना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान को घेरा। मनीष तिवारी ने कहा कि बैसरन घाटी में हुए उस दर्दनाक हमले को एक साल छह महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस दौरान जमीन पर क्या बदला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान ने इस हमले पर कोई अफसोस जताया है या वहां मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई है।

नवंबर 2026 तक पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठाए, विपक्ष ने मांगा जवाब : मनीष तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की पुरानी मांग आज भी वही है कि पाकिस्तान को भारतीय धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा देना पूरी तरह बंद करना होगा। उन्होंने याद दिलाया कि पहलगाम में निर्दोष लोगों को धर्म के नाम पर निशाना बनाकर बेरहमी से मार दिया गया था। ऐसे में यह सवाल आज भी कायम है कि नवंबर 2026 तक पाकिस्तान ने आतंकवाद के खात्मे के लिए आखिर क्या ठोस कदम उठाए हैं। बहरहाल, तमाम सियासी सवालों और कूटनीतिक सख्ती के बीच मुसादिक मलिक का पूरा कार्यक्रम केवल एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम की बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने तक ही सीमित रखा गया है।

एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हुआ गोल्डी बराड़, गिरफ्तारी पर 8 करोड़ रुपये से ज्यादा का इनाम

वॉशिंगटन :भारत और कनाडा में कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने शिकंजा कस दिया है। एजेंसी ने सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को अपनी टेन मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स सूची में शामिल किया है। उसकी गिरफ्तारी में मददगार साबित होने वाली जानकारी देने वाले व्यक्ति को 10 लाख डॉलर यानी करीब 8 करोड़ रुपये से अधिक का इनाम देने की घोषणा की गई है। गोल्डी बराड़ को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आपराधिक नेटवर्क का उत्तरी अमेरिका में प्रमुख संचालक बताया गया है। एफबीआई के अनुसार, बिश्नोई गैंग पर अमेरिका और कनाडा में हत्या, अपहरण, रंगदारी, नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियारों से जुड़े अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं। अमेरिकी एजेंसी गोल्डी बराड़ को आपराधिक साजिश, रंगदारी के जरिए कारोबार चलाने और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में तलाश रही है। एफबीआई के लॉस एंजिलिस फील्ड ऑफिस के अधिकारी पैट्रिक ग्रैंडी ने उसे खतरनाक अपराधी बताते हुए कहा कि उसकी गिरफ्तारी एजेंसी की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

अमेरिकी अभियोग पत्र के मुताबिक, गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक रहा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि बिश्नोई भारत की जेल में रहते हुए मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों को संचालित करता था। अलग-अलग देशों में इस नेटवर्क को चलाने की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ समेत उसके अन्य सहयोगियों को सौंपी गई थी।

अभियोग पत्र में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में 18 जून, 2023 को एक प्रमुख सिख धार्मिक और राजनीतिक शख्सियत की हत्या का भी जिक्र किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि इस हत्या का आदेश लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने दिया था। हालांकि, ये आरोप हैं और मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

राफेल विमानों की संख्या पर ब्रिटिश मैगजीन के दावे से मचा बवाल, 4 जेट कम होने की रिपोर्ट को पूर्व एयर चीफ ने किया खारिज

नई दिल्लीः भारतीय वायुसेना की ताकत के प्रतीक राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। ब्रिटिश एविएशन मैगजीन फ्लाइटग्लोबल ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सक्रिय राफेल विमानों की संख्या में चार की कमी आई है। भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे, लेकिन मैगजीन ने अपनी सूची में वर्तमान में केवल 32 राफेल विमानों को ही ऑपरेशनल बताया है। बिना किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान के दावों पर मुहर लगाने की कोशिश करती इस रिपोर्ट पर पूर्व वाइस एयर चीफ नर्मदेश्वर तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेवा देने वाले नर्मदेश्वर तिवारी ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मैगजीन को अपने स्रोतों की दोबारा जांच करने की सख्त जरूरत है।

पहले 35 विमान बताए और अब 32 का दावा, पूर्व एयर चीफ ने खोली रिपोर्ट की पोलः पूर्व वाइस एयर चीफ नर्मदेश्वर तिवारी ने ब्रिटिश मैगजीन के विरोधाभासी आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए इसकी विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वही मैगजीन है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जारी अपनी रिपोर्ट में 35 सक्रिय राफेल विमानों का जिक्र किया था, लेकिन अब अचानक संख्या घटाकर 32 बता रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी उजागर किया कि कथित तौर पर जिस विमान को गिराए जाने का दावा करते हुए उसका टेल नंबर बताया गया था, वह विमान उसके बाद भी कई युद्धाभ्यासों में हिस्सा ले चुका है। ऐसे में मैगजीन की यह रिपोर्ट पूरी तरह तथ्यों से परे नजर आती है।

खबर छापकर जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला, मैगजीन ने नीचे जोड़ दिया कानूनी डिस्क्लेमरः ब्रिटिश एविएशन मैगजीन फ्लाइटग्लोबल ने भारतीय वायुसेना के विमानों की सूची जारी कर राफेल की संख्या को लेकर सनसनी तो फैला दी, लेकिन किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बेहद चालाकी से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ लिया है। मैगजीन ने इस जानकारी के ठीक नीचे एक छोटा सा नोट लगाया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि दी गई जानकारी में किसी भी तरह की गलती होने पर फ्लाइटग्लोबल की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके साथ ही मैगजीन ने राफेल विमानों की संख्या में कमी बताने वाले इस दावे के पीछे किसी भी आधिकारिक या पुख्ता स्रोत की जानकारी भी साझा नहीं की है। 34 हजार पाउंड लेने वाले पत्रकार की रिपोर्ट का लिया सहारा? गणतंत्र दिवस पर झूठ हुआ था बेनकाबः ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान लगातार भारतीय विमानों को गिराने का झूठा दावा कर रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बयानों में इसका जिक्र करते रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर फ्लाइटग्लोबल की इस रिपोर्ट का असली स्रोत क्या है। एक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए यह दावा सामने आया है कि मैगजीन ने इस रिपोर्ट के लिए पाकिस्तान समर्थक पत्रकार एलन वॉर्न्स की रिपोर्टिंग का सहारा लिया है। गौरतलब है कि वॉर्न्स को लेकर यह बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उन्हें 34,000 पाउंड का भुगतान किया था। वॉर्न्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि संघर्ष के दौरान भारत के चार राफेल विमान बीएस-001, बीएस-021, बीएस-022 और बीएस-027 गिरे थे, लेकिन जब गणतंत्र दिवस के भव्य फ्लाईपास्ट में बीएस-022 ने आसमान में गर्जना करते हुए उड़ान भरी, तो उनके ये सारे दावे पूरी तरह झूठे साबित हो गए।

पायलट शिवांगी सिंह से लेकर र-400 तक, हर बार दुनिया के सामने पकड़ा गया पाकिस्तान का झूठः यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारतीय सेना को लेकर पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ हो। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने यह झूठ भी फैलाया था कि भारतीय महिला पायलट शिवांगी सिंह का जेट गिरा दिया गया है और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया है,

न्यूज IN ब्रीफ

उत्तर प्रदेश में 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील

नई दिल्ली / लखनऊ : भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन भारत तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मा० संजीव कुमार सिंहजी ने उत्तर प्रदेश की जनता, कांग्रेस कार्यकताओं, युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, अधिवक्ताओं तथा बुद्धिजीवियों से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत समर्थन देकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की है।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण राज्य है। यहां कांग्रेस को मजबूत करना केवल एक चुनावी लक्ष्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय, रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा और आम जनता के अधिकारों को मजबूत करने का अभियान है।मा० संजीव कुमार सिंहजी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। आज आवश्यकता है कि कांग्रेस की विचारधारा, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनकल्याणकारी राजनीति को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए।उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जनता से विशेषद अपील मा०संजीव कुमार सिंहजी ने उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहाःवर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं।

होटल में चली गोली ,जांच में जुटी पुलिस

हजारीबाग : हजारीबाग में गोलीबारी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों ने लगातार दूसरे दिन राहुल दुबे गिरोह के नाम पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। ताजा मामला चौपारण थाना क्षेत्र के सरदारपुर स्थित होटल एके इंटरनेशनल का है, जहां गुरुवार की देर रात अपराधियों ने होटल के बाहर कई राउंड फायरिंग की।
गोलीबारी में होटल के मुख्य प्रवेश द्वार का शीशा टूट गया। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी और दहशत का माहौल बन गया। 30 अक्टूबर को भी इसी होटल के मेन गेट पर फायरिंग की गई थी। इधर, घटना की सूचना मिलते ही चौपारण थाना प्रभारी पंकज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से राहुल दुबे गिरोह के नाम का एक पर्चा मिला है। बताया जा रहा है कि इस पर्चे के जरिए गिरोह ने घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। गौरतलब है कि 18 नवंबर की रात केरेडारी थाना क्षेत्र के पगार ओपी स्थित कोयला खनन कंपनी ऋत्विक के मुख्य गेट पर भी गोलीबारी हुई थी। वहां से पुलिस ने तीन खोखा बरामद किया था। इस घटना के बाद भी राहुल दुबे गिरोह के नाम की चर्चा सामने आई थी। लगातार दो दिनों में हुई गोलीबारी और इससे पहले होटल को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने जिले के कोयला कारोबारियों और अन्य व्यवसायियों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान, फायरिंग के पीछे की वजह और दोनों घटनाओं के बीच संभावित संबंधों का पता लगाने में जुटी है।

शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय की नई पहल

हजारीबाग : विनोबा भावे विश्वविद्यालय में शोध कार्यों को अधिक व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप शोध से जुड़ी प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की इस पहल से शोध कार्यों में पारदर्शिता आएगी और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चन्द्र भूषण शर्मा शोध के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके तहत विश्वविद्यालय में कई कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। साथ ही शिक्षकों को बड़े शिक्षण एवं शोध संस्थानों में अनुभव प्राप्त करने के लिए भी भेजा गया है।
इसी क्रम में 20 नवंबर को विश्वविद्यालय की ओर से एक पत्र जारी कर सभी संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों को नई व्यवस्था की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार शोध से संबंधित सभी प्रस्ताव एवं कार्य पहले विभागीय शोध परिषद (डीआरसी), विभागाध्यक्ष और संबंधित संकायाध्यक्ष के माध्यम से निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, ऊष्मायन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
गौरतलब है कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2026 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूगर्भ विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. एच.एन. सिन्हा को निदेशक, अनुसंधान, नवाचार, ऊष्मायन, उद्योग संपर्क एवं उद्यमिता नियुक्त किया है। नई व्यवस्था को विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

आईसीएआर-आईएआरआई में 30 जनजातीय किसानों का मुर्गी पालन प्रशिक्षण संपन्न

बरही : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान गौरियाकरमा में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के तहत आयोजित तीन दिवसीय बैकयार्ड कुक्कुट पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हुआ। 18 से 20 नवंबर तक चले इस प्रशिक्षण में 30 अनुसूचित जनजाति के किसानों ने भाग लिया। संस्थान के निदेशक डॉ. सी. एच. श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम के समापन समारोह में कैंपस प्रभारी डॉ. एस. के. महंता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों से प्रशिक्षण में सीखी गई वैज्ञानिक तकनीकों को अपने गांवों में अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कम लागत में मुर्गी पालन ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने का बेहतर माध्यम बन सकता है।
प्रशिक्षण के दौरान किसानों को मुर्गी पालन की आधुनिक तकनीक, रोग प्रबंधन, संतुलित आहार और विपणन की जानकारी दी गई। समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। प्रत्येक किसान को 1.5 किलोग्राम मक्का, सब्जी किट और पशुपालन संबंधी आवश्यक दवाइयां भी वितरित की गईं। मौके पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. विशाल नाथ, डॉ. वंदना, टीएसपी नोडल अधिकारी डॉ. मुकेश तिवारी, डॉ. शिल्पी केरकेट्टा, बादल कुमार और कैलाश वर्मा उपस्थित रहे।

वॉलीबॉल टूर्नामेंट में चौपारण ने ताजपुर को हराकर जीता खिताब

चौपारण/बरही : चौपारण में पहली बार रात्रिकालीन सीपीएल (चौपारण प्रीमियर लीग) वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। दूधिया रोशनी में खेले गए इस टूर्नामेंट में मेजबान चौपारण की टीम ने ताजपुर को हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में आठ टीमों ने हिस्सा लिया। चौपारण पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विनोद कुमार सिंह की पहल पर आयोजित प्रतियोगिता में चौपारण, ताजपुर, पपरो, चयकला, अमझर, इंगुनिया, चौपारण बी और मयूरहंड प्रखंड के बनहे की टीम शामिल हुई। सभी मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में चौपारण ने चौपारण बी को तथा ताजपुर ने पपरो को हराकर फाइनल में जगह बनाई। खिताबी मुकाबले में चौपारण और ताजपुर के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला।

छठ पूजा की सफलता पर समिति ने की समीक्षा अगले साल और भव्य आयोजन का निर्णय

विधायक सुखराम उरांव ने सभी सहयोगियों और शहरवासियों का जताया आभार

संवाददाता

चक्रधरपुर : केंद्रीय छठ पूजा समिति की समीक्षा बैठक शुक्रवार को नगर परिषद सभागार में विधायक सुखराम उरांव की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में इस वर्ष छठ महापर्व के सफल आयोजन को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान समिति की ओर से पूजा आयोजन में हुए आय-व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।
बैठक में विधायक सुखराम उरांव ने छठ पूजा के सफल आयोजन पर समिति के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों, नगर परिषद कर्मियों एवं शहरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व आस्था, स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक एकता का प्रतीक है। चक्रधरपुर में छठ



पूजा का सफल आयोजन सभी के सामूहिक प्रयास, सहयोग और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से ही इतने बड़े धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जा सका।
विधायक ने आगे कहा कि अगले वर्ष छठ महापर्व का आयोजन और अधिक भव्य एवं आकर्षक बनाने के लिए अभी से योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की जाएगी। घाटों की बेहतर व्यवस्था, साफ-सफाई, रोशनी और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में आगामी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी घाटों में आकर्षक सजावट, विशेष रोशनी एवं भंडारे के आयोजन को लेकर भी चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आपसी सहयोग से कार्य करने पर सहमति जताई।
बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने आगामी वर्ष छठ महापर्व को और बेहतर तरीके से आयोजित करने का संकल्प लिया।

सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण

संवाददाता

पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वैशाली जिले में कच्ची दरगाह-राजापाकर-बिदुपुर छह लेन पुल (नीतीश सेतु) का निरीक्षण किया तथा 21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने 'नीतीश सेतु के पिलर संख्या 23 एवं 24 के बीच बनाए गए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने वहां मंच निर्माण, सुरक्षा, यातायात, आगंतुकों की सुविधा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों से प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां निर्धारित समय पर पूरी की जाएं तथा सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के क्रम में अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रखने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक श्री संजय सरावगी, विधायक श्री मंगल पांडेय, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रदेश प्रभारी श्री हरीश द्विवेदी, भाजपा के संगठन महामंत्री श्री भीखू भाई दलसानिया, पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय कुमार सिंह, वैशाली की जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

पिपा पुल आपने बदहाली को लेकर चर्चा में

समाजसेवी रामजी राय की मांग, दुरुस्त हो दानापुर पिपा पुल

संवाददाता

पटना : दियारा की लाइफ लाइन कहे जाने वाली दानापुर पिपा पूल, का काम अभी तक अधूरा? ग्रामीणों को हो रही है काफी असुविधा, समाजसेवी रामजी राय की माँग है कि इस महीने के अंत तक पिपा पूल शुरू किया जाए!
अधिकांश बिहार का पीपा पूल शुरू हो गया है, मगर पिपा पूल का जनक कहे जाने वाले दानापुर



पिपा पूल का काम अभी तक अधूरा है। दानापुर पिपा पूल बिहार का प्रथम पिपा पूल है, जिसकी शुरूआत माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इसकी शुरूआत कर पहली बार सहर को गावों से और गावों को सहर से जोर कर एक क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं।
आज वही धरोहर पिपा पूल की निर्माण को अनदेखा किया जा रहा है। बिहार में पूल क्रांति के अहम भूमिका निभाई है दानापुर पिपा पूल,भले ही आज बड़े-बड़े पूल की निर्माण हो गई और हो रही है बिहार में, मगर बिहार के लोगों खास कर सारण, पटना जिला की जीवन सेतु की भूमिका अदा की है यही दानापुर पिपा पूल, इतना लोकप्रिय किसी भी पूल को बिहार में नहीं मिला, आज यही पिपा पूल अपने हालत को लेकर और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण खस्ता हालत में है?

7 जनवरी को होगा विजैया पैक्स प्रबंध समिति का चुनाव

बरही : विजैया पैक्स प्रबंध समितियों का चुनाव 7 जनवरी 2027 को होगा। इसके लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया 24 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। यह आदेश जिला अश्विनी कुमार ओझा, सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, हजारीबाग सह संचालन पदाधिकारी, झारखंड की ओर से जारी किया गया है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी संजय कुमार यादव को निर्वाचन पदाधिकारी और सहायक सहकारिता पदाधिकारी सुनील कुमार प्रसाद अनुकल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 24 दिसंबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक नामांकन होगा। दोपहर 12 से 2 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2:30 बजे नामांकन पत्रों की सूची जारी की जाएगी। 26 दिसंबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक नामांकन पर आपत्तियां ली जाएंगी।

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर विभावि में विशेषज्ञों ने रखे विचार

प्राकृतिक जीवनशैली अपनाने से ही संभव है बेहतर स्वास्थ्य

ऑनलाइन परिचर्चा में स्वास्थ्य के प्राकृतिक उपायों पर हुई चर्चा

संवाददाता

हजारीबाग : नौवें राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के योग केंद्र की ओर से कौशाम्बी योग सर्किल एवं दिव्य करुणा संगठन, हरिद्वार के सहयोग से ऑनलाइन विशेषज्ञ वार्ता सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। ह्यप्रकृति के अनुसरण से आरोग्यह्व विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने प्राकृतिक जीवनशैली अपनाने और प्राचीन स्वास्थ्य सिद्धांतों के महत्व पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए योग केंद्र के निदेशक डॉ. राजकुमार चौबे ने कहा कि आज अप्राकृतिक जीवनशैली का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को प्रकृति की ओर लौटने की जरूरत है। प्राचीन स्वास्थ्य सिद्धांतों का धैर्य और अनुशासन के साथ पालन करने से स्वस्थ जीवन प्राप्त किया जा सकता है।
विशेषज्ञ वक्ता के रूप में श्रीराम आयुष चिकित्सालय, लखनऊ के श्री दीपांकर आत्रेय और राजस्थान के प्रतापगढ़ से डॉ. लोकेश चौधरी शामिल हुए। दीपांकर आत्रेय ने प्रकृति के बाहरी और आंतरिक पक्षों की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान भोगवादी जीवनशैली में प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों का विशेष महत्व है। प्राकृतिक चिकित्सा रोगों के मूल कारण यानी शरीर में मौजूद विजातीय तत्वों के शोधन पर आधारित है। वहीं, डॉ लोकेश चौधरी ने कहा कि प्रकृति के संकेतों के अनुरूप जीवनशैली अपनाकर स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने बदलते मौसम के अनुसार आहार-विहार में बदलाव के महत्व को समझाया। साथ ही शरीर शोधन के विभिन्न प्राकृतिक उपायों की जानकारी दी।
कार्यक्रम में दोनों विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा सत्र भी आयोजित किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े विभिन्न सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने जवाब दिया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन योग केंद्र के शिक्षक अनुराग जायसवाल ने किया। मौके पर योग प्रशिक्षिका सुरभि सिंह, प्रशिक्षक सत्यप्रकाश, विद्यार्थी साक्षी सिंह, रेखा, हेमा ठाकुर सहित अन्य विद्यार्थी और बाहरी प्रतिभागी उपस्थित थे।

चक्रवात के खतरे को लेकर किसानों को सतर्क रहने की सलाह

संवाददाता

रामगढ़ : अकवान चक्रवात के कारण संभावित भारी बारिश और खराब मौसम की आशंका को देखते हुए रामगढ़ जिला प्रशासन ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उपायुक्त ऋतुराज के निर्देश पर जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग ने फसल सुरक्षा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
प्रशासन ने किसानों से संभावित तेज हवाओं और बारिश से खड़ी फसलों तथा खेतों में रखी कटी हुई उपज को बचाने के लिए समय रहते एहतियाती कदम उठाने की अपील की है। जारी निर्देश के अनुसार, अधिसूचित स्थानीय आपदा अथवा फसल कटाई के बाद खेत में रखी उपज को नुकसान पहुंचने की स्थिति में बीमित किसानों को घटना के 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना देना अनिवार्य होगा।
फसल नुकसान की जानकारी कृषि रक्षक पोर्टल, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बीमा कंपनी, नजदीकी पैक्स अथवा प्रखंड कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती है।
वहीं, खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान होने की स्थिति में बीमा इकाई स्तर पर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के वास्तविक उपज आंकड़ों के आधार पर क्षति का आकलन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए किसानों को व्यक्तिगत रूप से नुकसान की सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों, बीमा कंपनियों और पैक्स को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही किसानों तक समय पर आवश्यक जानकारी पहुंचाने और फसल क्षति की रिपोर्टिंग एवं आकलन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कोई भी पात्र किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित न रहे।

अंडरपास की मांग पर अड़े कुल्ही के ग्रामीण, निर्माण कार्य का किया विरोध

रामगढ़ : जिले के दुलमी प्रखंड अंतर्गत कुल्ही में अंडरपास निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक निर्माण की दिशा में ठोस पहल नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। इसी बीच सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदारों द्वारा ग्रामीणों की मांगों का समाधान किए बिना काम कराने की कोशिश पर लोगों ने विरोध जताया। मामले को लेकर कुल्ही में ग्रामीणों, रजरप्पा थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पदाधिकारियों और सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदारों के बीच वार्ता हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखते हुए अंडरपास निर्माण की मांग दोहराई। ग्रामीणों ने कहा कि कुल्ही में अंडरपास निर्माण की मांग काफी पुरानी है। इस संबंध में पूर्व में कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी ओर, निर्माण कंपनी के ठेकेदार ग्रामीणों की मांगों को नजरअंदाज कर जबरन काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब अंडरपास निर्माण का आश्वासन दिया गया है, तो उस पर अमल किए बिना निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, अंडरपास नहीं बनने से स्थानीय लोगों के आवागमन में परेशानी होगी। खासकर किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और आसपास के गांवों के लोगों को रोजमर्रा के कामों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुल्ही में अंडरपास का निर्माण क्षेत्र की जरूरत है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी इस मामले में लगातार प्रयास कर रहे हैं और संबंधित स्तर पर पहल कर रहे हैं। इसके बावजूद निर्माण कंपनी द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। वार्ता के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन, एनएचएआई और निर्माण कंपनी के अधिकारियों से अंडरपास निर्माण पर स्पष्ट एवं ठोस निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर स्थानीय लोगों की सुविधा, सुरक्षा और अधिकारों से समझौता स्वीकार नहीं करेंगे।

नशामुक्ति को लेकर कुरुचडेगा ग्रामसभा का बड़ा फैसला

अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

संवाददाता

सिमडेगा/कुरुचडेगा : नशामुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से शनिवार को कोनसोदे पंचायत अंतर्गत कुरुचडेगा गांव में व्यापक नशामुक्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रातः 10 बजे ग्रामसभा अध्यक्ष सुकरा केर-केट्टा की अगुवाई में ग्रामसभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से गांव के सभी टोलों में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया।ग्रामसभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गांव के किसी भी टोले में अवैध रूप से शराब का निर्माण एवं बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस निर्णय का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ग्रामसभा द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित मामलों को पुलिस प्रशासन के पास भेजा जाएगा। निर्णय को प्रभावी ढंग से



लागू करने एवं इसकी निगरानी के लिए एक विशेष कमेटी का भी गठन किया गया। ग्रामसभा की बैठक के उपरांत नशामुक्ति के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशाल जागरूकता रैली एवं प्रभात फेरी निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष ग्रामीण शामिल हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए ह्लदारू चुलाई बंद करो, दारू पीना बंद करोह्व सहित नशामुक्ति से जुड़े विभिन्न नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। ग्रामीणों ने एकजुट होकर शराब के अवैध कारोबार और नशे की प्रवृत्ति को समाप्त करने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर गांव के सभी महिला मंडलों की सदस्य, वार्ड सदस्य, उपमुखिया सोमरा बुडिंग, पंचायत समिति सदस्य रेशमा बुडिंग, किसान मित्र किरण कंडूलना आंगनबाड़ी सेविका इसरानी बुडिंग सहित गांव के हजारों महिला एवं पुरुष ग्रामीण उपस्थित रहे।